● वर्ष-3
● अंक-214
रायपुर, गुरुवार
18 अप्रैल 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ये हैं वो हॉट कोर्सेस ग्रेजुएशन के बाद...

बस्तर समेत देश की 102 लोस सीटों पर थमा चुनाव प्रचार

घर घर पहुंचेंगे प्रत्याशी

नई दिल्ली/रायपुर। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 102 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले चरण में देश के 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाले हैं, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले यानी आज शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग-अलग समय पर समाप्त कर दिए गए है। इस तरह से इन संसदीय क्षेत्रों में आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंटा में मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रात: 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में प्रात: 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

उत्तर प्रदेश की जिन 08 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनोर, नगीना, मोरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल हैं। बिहार की चार सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इन चार सीटों में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट शामिल है। वहीं पहले चरण के मध्य प्रदेश की छह लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन छह सीटों में छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी, और शहडोल सीट शामिल है। महाराष्ट्र की जिन छह सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक, चंद्रपुर, भंडारा-गोंदिया, नागपुर सीट शामिल है। वहीँ छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा की एक मात्र सीट पर मतदान होंगे। तमिलनाडु की सभी की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु में अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों में नीलगिरी, कोयंबटूर, पोलाची, डिंडीगुल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, नागपट्टिनम, तंजावुर, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, श्रीपेरंबदूर, कांचीपुरम, अराक्कोनम, वेल्लोर, कृष्णागिरी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, अरणी, विलुप्पुरम, कल्लाकुरिची, सलेम, नामक्कल, इरोड, तिरुप्पुर, कुड्डालोर, चिदंबरम, मयिलादुथुराई, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, थूथुकुडी और तेनकासी सीट शामिल है।

सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी, मारे गए 29 माओवादी

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) को सुरक्षाकर्मियों ने 29 माओवादी आतंकियों को मार गिराया है। मंगलवार को बीएसएफ और डीआरजी के द्वारा किया गया यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि आखिर सुरक्षा बल के जवानों ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया और अब तक ऐसी कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही थी?

बस्तर रेंज के पुलिस आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि गुप्त सूत्रों से पुलिस को एक पॉजिटिव इनपुट मिला था कि उत्तर बस्तर डिवीजन के हार्डकोर माओवादी आतंकी शंकर राव, ललिता माड़वी, राजू समेत करीब 4 दर्जन से अधिक माओवादी क्षेत्र में मौजूद हैं। ये सभी माओवादी बीनागुंडा से हापाटोला के बीच रहकर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस जानकारी की पुष्टि होने के बाद मंगलवार को ही छोटेबेठिया से बीएसएफ और डीआरजी की एक संयुक्त टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए हापाटोला के जंगल की ओर भेजा गया।

इस दौरान दोपहर 2 बजे जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 29 नक्सली मारे गए। करीब साढ़े पांच घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने घटनास्थल की तलाशी ली तो उन्हें माओवादियों के शव, बड़ी संख्या में एके-47 रायफल, इंसास रायफल, थ्री नॉट थ्री बंदूक समेत गोला बारूद भी बरामद हुए।

ऑपरेशन की रणनीति

हापाटोला के जंगल में जिस तरीके से सुरक्षाकर्मियों ने माओवादियों को ढेर किया है, उसके पीछे की रणनीति पहले ही बन चुकी थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल के जवान इन अभियानों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। इस पूरे अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि जिस अबूझमाड़ से लगे क्षेत्र में फोर्स ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है, वह अत्यधिक कठिन क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ का यह ऑपरेशन पूरी तरह इंटेलिजेंस के आधार पर था, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन से पहले दो दिन से बीएसएफ को इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे, जिसके बाद ही इस अभियान की योजना बनाई गई। बीएसएफ अधिकारी के अनुसार पुलिस और बीएसएफ की टीम उस पूरे क्षेत्र में बीते महीने से ही नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही थीं। चूंकि यह क्षेत्र नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, इसीलिए बीएसएफ और पुलिस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया। बदले हुए रणनीति के तहत फोर्स ने हार्ड परस्यूड और ट्राय फ़ॉर हंट की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने कम समय में ही आक्रामक अभियान किए और सीधे मुठभेड़ों में माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। बीएसएफ डीआईजी के अनुसार नक्सलियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पहाड़ियों की पूर्वी दिशा से ऑपरेशन करेंगे, जिसके कारण उनकी पूरी साजिश धरी की धरी रह गई, और इसी कारण पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े स्तर के इतने माओवादी आतंकी एक साथ मारे गए हैं।

क्यों नहीं मिल रही थी सफलता

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 से 2023 के बीच भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इस सरकार के दौरान ना सिर्फ नक्सलियों के हौसले बुलंद थे बल्कि नक्सली भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग भी कर रहे थे। पूरे बस्तर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलियों ने अपने संगठन में विस्तार किया और विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं भूपेश सरकार की नीतियों, उनके कम्युनिस्ट सलाहकारों और नक्सल सहानुभूति के चलते स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि हमारे सुरक्षा बल के जवान मारे जा रहे थे। सीआरपीएफ के ही अधिकारी ने कहा था कि भूपेश सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के कैंप की जानकारी सार्वजनिक किए जाने के कारण फोर्स के जवान बेवजह मारे जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर आक्रामक ऑपरेशन नहीं चलाने का दबाव और साथ ही अर्बन नक्सलियों से सांठगांठ ने बस्तर को एक बार फिर लाल आतंक के साये में धकेल दिया था।

सत्ता परिवर्तन के बाद बदली तस्वीर

प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद जैसे भाजपा ने कमान संभाली, वैसे ही पहले तो माओवादियों ने जमकर आतंक मचाया, आगजनी की, ग्रामीणों की हत्या की, भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग्स हुई, लेकिन इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने राजधानी रायपुर में बैठक ली, जिसने बस्तर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। जनवरी 2024 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माओवाद की समस्या पर समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि माओवादियों के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाया जाए।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के मुखिया तपन कुमार डेका ने रायपुर का दौरा किया था और दो दिनों तक अधिकारियों की बैठक ली थी।

करीब 6 घण्टे से अधिक समय तक चली इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और सीआरपीएफ के प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे। वहीं इस बैठक में पड़ोसी राज्यों समेत 10 राज्यों के शीर्ष अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद थे। इस बैठक के बाद भी सुरक्षा बल के जवानों ने माइक्रो लेवल पर टारगेट बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए, जिसकी पहली सफलता ही प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हो चुकी है।

गृहग्राम बगिया में मुख्यमंत्री ने मनाई रामनवमी

रायपुर/बगिया। मुख्यमंत्री के गृहग्राम बगिया में आज रामनवमी की धूम रही। आसपास के पचास से अधिक गांव के पांच हजार लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ पूजा में भाग लिया। विष्णु देव साय ने अपनी अर्धांगिनी कौशल्या साय के साथ मां दुर्गा की उपासना की और प्रसाद का भोग लगाया। गौरतलब है कि पिछले तीन पीढ़ियों से मुख्यमंत्री का परिवार नवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास से मनाता है।

प्रमोशन में आरक्षण: भूपेश सरकार का आदेश निरस्त

बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2019 के राज्य सरकार के आदेश को पूर्णत: निरस्त कर दिया है. इससे पहले अदालत ने इस पर रोक लगाई थी. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पूरे केस की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिका निराकृत कर दी है. 5 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

बता दें कि, राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी. इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा.

प्रमुख समाचार

आजाद ने किया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान

जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले, पूर्व कांग्रेस नेता को डीपीएपी ने अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र से नामांकित किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को अनंतनाग में एक बैठक में यह घोषणा की। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। उधमपुर में जीएम सरूरी लड़ रहे हैं। आजाद को सीएम रहने के दौरान जम्मू में कराए गए कामों के लिए पसंद किया जाता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कठुआ बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लाल सिंह का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया। वे बीजेपी से भी बदतर हैं। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक वह जेल नहीं जाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे। जेल का क्या हुआ?

टीएमसी का घोषणा पत्र: सीएए कानून होगा रद्द, यूसीसी नहीं होगा लागू,

कोलकाता। चुनाव का पहला चरण शुरू होने से दो दिन पहले बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पहले चरण में कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा। घोषित 10 वादों में पार्टी संयोजक ममता बनर्जी का बार-बार दोहराया गया आश्वासन शामिल है कि बंगाल में कोई नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नहीं होगी। घोषणापत्र में सीएए को खराब बताया गया और कहा गया कि इसे खत्म कर दिया जाएगा और एनआरसी को बंद कर दिया जाएगा। तृणमूल नेताओं ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को तृणमूल के समर्थन पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में सरकार बनने के बाद वादे पूरे किए जाएंगे, हालांकि राज्य में कोई गठबंधन नहीं है।

चुनाव आयोग ने राज्यपाल के कूच बिहार दौरे को रद्द करने की दी सलाह

कोलकात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चुनाव आयोग ने 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार का अपना दौरा रद्द करने की सलाह दी है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रस्तावित दौरा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पहले चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि बुधवार शाम से लागू होगी। मौन अवधि उस समय को संदर्भित करती है जब राजनीतिक दलों को मतदान तिथि से पहले प्रचार करने से रोक दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत राज्यपाल के लिए उनके जारी कार्यक्रम में प्रस्तावित कोई भी स्थानीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने यह भी नोट किया है कि 18 और 19 अप्रैल के दौरान पूरा जिला प्रशासन और पुलिस बल चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल से जून तक सात चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा. वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को बताया शहीद

नई दिल्ली/ रायपुर। कांकेर में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसमें नक्सलियों के कुछ बड़े कमांडर भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया। कहा कि बीजेपी की सरकार में फर्जी मुठभेड़ होते हैं। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अब इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का विवादित बयान सामने आया है। सुप्रिया का यह बयान सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। इसमें सुप्रिया से कांकेर में नक्सली मुठभेड़ और बघेल के बयान के संदर्भ में सवाल किया गया है। पूछा गया कि बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस पर सुप्रिया ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और उन सब लोग जो शहीद हुए, मारे कुछ सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं, उन सबको हमारी संवेदना है। इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है।

'आप' ने लोस चुनाव से पहले 'आप का रामराज्य' वेबसाइट लॉन्च की

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान के तहत बुधवार को अपनी 'आप का रामराज्य' वेबसाइट

लॉन्च की, जिसका उद्देश्य पार्टी के राम राज्य के दृष्टिकोण को चित्रित करना है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में भगवान राम के आदर्शों को मूर्त रूप देने के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों पर जोर दिया गया। वेबसाइट aap-karamrajya.com का लॉन्च रामनवमी उत्सव के साथ हुआ और लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले हुआ, जिसका पहला चरण शुक्रवार, 19 अप्रैल को होना है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वेबसाइट पार्टी की सरकारों की उपलब्धियों के साथ-साथ आप की राम राज्य की व्याख्या को प्रदर्शित करेगी। सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राम राज्य को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में अद्भुत चीजें-अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त पानी और बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा-हासिल कीं।

राजनीति में अनुकरण की रणनीति

प्रभु चावला

राजनीति अतिरेकों से बुनी होती है, जिसमें स्मृति और विस्मृति के डिजाइन होते हैं। दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी तमिलनाडु में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जीके मूपनार के लिए प्रचार कर रहे थे। वे लोग दूर-दराज के एक टोले में स्थित एक झोपड़ी में गये। मूपनार ने वहां रहने वाली बूढ़ी महिला से पूछा कि क्या वह राजीव को पहचानती है। उसने तुरंत जवाब दिया- 'हां, ये इंदिरा अम्मा के बेटे हैं। आप कौन हैं?' यह जवाब कांग्रेस और अन्य दलों के व्यक्तिगत और वंशगत कुलीनता के विरोधाभास को बिंबित करता है। मतदाता प्रधानमंत्री को जानते थे, पर क्षेत्रीय नेता को नहीं। इस चुनाव के नतीजे ने यही साबित किया। विधानसभा की 234 सीटों में कांग्रेस को केवल 26 सीटें मिलीं तथा उसे 20 प्रतिशत से भी कम वोट मिले। हालांकि 2024 का साल 1989 नहीं है, पर लगभग सभी राज्यों में स्मृति का हाल वैसा ही है। पूर्व में इटानगर से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक मतदाता तुरंत सर्वव्यापी नरेंद्र मोदी से जुड़ जाते हैं। लेकिन उनमें से आधे से अधिक ने भाजपा या उसके स्थानीय प्रत्याशी को नहीं चुना है। पहली बार आम चुनाव मुद्दों की किसी एक राष्ट्रीय सूची के बिना हो रहा है। हर क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दे हैं, पर व्यक्तिगत सर्वोच्चता सामान्य बात बन गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यम, संदेश और संदेशवाहक एक ही व्यक्ति है- नरेंद्र मोदी। प्रचार अभियानों में उनके समर्थक उनकी वैचारिक अभिव्यक्तियों से कहीं अधिक उनके व्यक्तित्व, हाव-भाव और मानसिक क्षमता से प्रभावित होते हैं। इस रणनीति से उन्हें बड़े लाभ हुए हैं और शायद तीसरी बार भी उन्हें रिकॉर्ड सफलता मिले।

राजनीति में अनुकरण रणनीति का एक रूप है। कई क्षेत्रीय खिलाड़ी मोदी की नकल मात्र हैं। स्थानीय चुनावी आख्यान शासन के वैकल्पिक रूपों के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि क्षेत्रीय नेताओं के चारों ओर घूमता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, मुख्यमंत्री और संदेशवाहक हैं। वहां वोट या तो उनके पक्ष में होगा या विरोध में। ऐसा कर्नाटक में डीके शिवकुमार और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान के पक्ष या विरोध में मतदान होगा। ऐसे अन्य क्षेत्रीय नेता बिहार में तेजस्वी यादव, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केरल में पिनराई विजयन हैं।

दुखद है और अचरज की बात भी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी वैकल्पिक संदेशवाहक नहीं बन सके। सभी पार्टियों के लिए मुद्दे या तो तभी उठाने के लिए हैं, जब बहुत जरूरी हो या ध्यान भटकाना हो। राजनीतिक विमर्श क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। उत्तर भारत में 'फूट डालो और राज करो' के तरीके के लिए संस्कृति, राजनीति और धर्म शिकार के मैदान हैं। लगभग 60 प्रतिशत सीटों पर मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य खिलाड़ी हैं, पर बाकी राज्यों में मोदी ही महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री केवल सांकेतिक दूसरा इंजन भर हैं।

सभी राज्यों में भाजपा विकास का कार्ड खेल रही है, पर अंतत: उसका अभियान हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इसको जोड़ने वाला सूत्र मोदी का दृढ़ निश्चय है- अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर, पाकिस्तान पर लगाम और जोर-शोर के साथ गिरफ्तारियों से आतंक को कम करना। प्रधानमंत्री की सभाओं में भाजपा के मुख्यमंत्री महज कट-आउट हैं। दूसरी ओर, अखिलेश, तेजस्वी, मान, केजरीवाल, अब्दुल्ला और महबूबा अपने को मोदी के स्थानीय विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत (130 सीटें) एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां मोदी का सीधा मुकाबला ताकतवर स्थानीय क्षत्रपों से है। इसीलिए वे दक्षिणी राज्यों के अधिक दौरे करते हैं। भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने का उनका लक्ष्य पांच दक्षिणी राज्यों के नतीजों पर निर्भर करता है। भाजपा ने ऐसा कोई स्थानीय नेता नहीं तैयार किया है, जिसका जनाधार पूरे राज्य में हो। अन्नामलाई को मीडिया में खूब जगह मिली है, पर उन्हें अभी जमीन पर ठीक-ठाक स्वीकार्यता हासिल करनी है। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ी है, पर तमिल और मलयाली वोटरों की चेतना में कमल खिलना अभी बाकी है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक की सर्वाधिक लोकप्रियता है। भाजपा के स्थानीय नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया-शिवकुमार की जोड़ी की कोई बराबरी नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में लड़ाई मोदी बनाम शेष है।

ऐसा लगता है कि यह चुनाव अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने और सामने खड़े विपक्षियों को खत्म कर देने के लिए व्यक्तिगत नेताओं के बीच एक कटुतापूर्ण युद्ध है। यह वैश्विक स्तर पर विचारधारा के वैयक्तीकरण का दौर है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है : सुंदरराज पी

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटेबेठिया एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। इस संबंध में बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने प्रेस कांफ्रेस कर जानकारी दी है। उन्होंने माओवादियों के डेड बॉडी रिकवरी के नजरिए से इस मुठभेड़ को छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल ऑपरेशन में सबसे बड़ा बताया। उन्होंने माओवादियों के खिलाफ मिली बढ़त को बनाए रखने की बात कही है।

बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बताया, 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटेबेठिया क्षेत्र में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके बाद डीआरजी टीम और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम रवाना की गई थी। सुबह से इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे थे। अभियान के दौरान दोपहर 2 बजे से लगातार 4 घंटे तक सुरक्षबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबलों की अलग अलग टुकड़ियों ने बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों को जवाब दिया।

आईजी सुंदरराज पी ने कहा मुठभेड़ के बाद कुल 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। उनमें से 15 महिला नक्सली और 14 पुरुष नक्सलियों के शव रिकवर किए गए थे। अभी सभी शवों की शिनाख्ती की जा रही है। इनमें 2 बड़े नक्सलियों डीवीसी शंकर और डीवीसी ललिता का पहचान हुई है। बाकी

शवों के शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है।

बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने कहा, पिछले तीन चार महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी जिलों में प्रभावी रूप से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप 2024 में अब तक कुल 71 माओवादियों के शव रिकवर किए गए हैं। पिछले हमलों और ऑपरेशन के अनुभवों से सीखर हम आगे कार्रवाई कर रहे है। आईजी सुंदरराज पी ने कहा नक्सलियों के खिलाफ यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि जो बढ़त हमको हासिल हुई है, उसे सावधानी पूर्वक बरकरार रखें। ताकि नक्सलियों का असली चेहरा, विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा लोगों के सामने आए। लोग नक्सलियों से मुक्ति पाने के इंतेजार में हैं।

बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बताया, घटनास्थल से एके-47, एसएलआर, 2 इंसास, एलएमजी, एक कार्बाइन,9 एमएम पिस्टल और भारी मात्रा में अन्य गोला बारूद और वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर किए गए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी भी कल के मुठभेड़ में हुई है। इन हथियारों के बारे में पतासाजी की जा रही है कि कौन कौन से घटनाक्रम में इन हथियारों को सुरक्षाबलों से लूटा गया था।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में 17 अप्रैल को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करने की तैयारी चल रही है। 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कांकेर में हुई मुठभेड़ में कुल 29 नक्सली मारे गए थे और तीन सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे।

एएसपी मनीषा ठाकुर ने कहा बरामद सभी शवों को अस्पताल लाया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ शवों की पहचान होनी बाकी है। प्रशासन की टीम मौजूद है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी यहां हैं और एफएसएल की टीम भी यहां है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। बस्तर के सभी जिलों में सुरक्षा टाइट है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। हालांकि, कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन उसके पहले मंगलवार को कांकेर में सुरक्षाबलों ने नक्सल मोर्चे पर बड़ा प्रहार कर दिया है।

नारायणपुर में नक्सलियों ने की भाजपा नेता की हत्या

नारायणपुर। लोकसभा चुनाव पहले नक्सलियों ने बस्तर में एक बार फिर उत्पात मचाकर दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। बीती रात नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में भाजपा नेता की हत्या कर दी है। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद इलाके में जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाया गया है।

नारायणपुर जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के दण्डवन गांव का भाजपा नेता और गांव का उपसरपंच पंचम दास बीती रात अपने घर में मौजूद था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम उसके घर पहुंची। घर का दरवाजा तोड़कर घुसे नक्सली भाजपा नेता को उठाकर अपने साथ कुछ दूर सुनसान इलाके में ले गए और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली शव को फेंककर चले गए। इस घटना की पुष्टि नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने की है। बस्तर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने पंचम दास को शक्तिकेंद्र सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी थी। क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए चुनाव प्रचार का काम कर रहा था। एसपी प्रभात कुमार ने कहा नक्सलियों ने 1 ग्रामीण की हत्या कर दी है। ग्रामीण का नाम पंचमदास है। जो दण्डवन गांव में उपसरपंच के पद पर था। आस पास क्षेत्र में पुलिस बल, डीआरजी, सर्च ऑपरेशन चला रही है।

गांव में उपसरपंच और भाजपा नेता की हत्या के बाद इलाके में दशहत का माहौल हो गया है। इस घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुबह पुलिस बल को घटना स्थल के लिये रवाना किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा। जवानों ने इलाके में सर्चिंग अभियान शुरू किया।

हत्या के बाद नक्सलियों ने घटना स्थल के आसपास जगह जगह बैनर बांधे हैं। साथ ही कई पर्चे भी फेंके हैं। बैनर पर्चों में नक्सलियों ने भाजपा नेता पंचम दास पर जनविरोधी, भ्रष्टाचार और पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है।

बैनर पोस्टर में चुनाव बहिष्कार के नारे भी लिखे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अमित भद्र व सरपंच बिसेल नाग को मौत की सजा देने की बात पर्चों और बैनर में लिखी हैं। नक्सलियों ने बीते विधानसभा चुनाव के पहले सागर साहू और रतन दुबे की हत्या का भी जिक्र किया है। खदान में लगे ट्रक चालक व परिवहन संघ के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी है। हत्या की वारदात को नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने अंजाम दिया है।

कांकेर में मुठभेड़ के बाद ली गई तलाशी, भारी मात्रा में मिला एके-47, गोला बारूद समेत हथियार

छत्तीसगढ़ के कांकेर में फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने के बाद इलाके की तलाशी ली गई। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। कांकेर में एंटी-नक्सल ऑपरेशन पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एके-47 और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। आम तौर पर इन हथियारों का इस्तेमाल वरिष्ठ माओवादी करते हैं। इन हथियारों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नक्सली हिंसक गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रची थी। विधानसभा चुनाव के समय हमने उचित व्यवस्था की थी, इसलिए वे ऐसे घटना को अंजाम नहीं दे पाए। कोई भी बड़ी घटना हो और इस वक्त भी हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उस पर हमारा काम है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बस्तर और कांकेर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा।

गीदम में ही बने मेडिकल कॉलेज-व्यापारी संघ

हर वर्ग को मेहनत और समर्पण व्यापरियों से सीखनी चाहिए-चैतराम

गीदम। आम चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के व्यापार एवं आर्थिक प्रकोष्ठ की बैठक व्यापारी संघ गीदम के समस्त व्यापारियों के साथ मंगलवार शाम को दुर्गा पंडाल पी डब्लू डी पारा गीदम में रखी गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चैतराम अटामी मौजूद रहे। बैठक में नगर के व्यापारियों से उनकी समस्या एवं मांगो को विधायक चैतराम अटामी ने विस्तार पूर्वक एवं गंभीरता से सुना। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज गीदम में खुलने की घोषणा हुई थी। किंतु मेडिकल कॉलेज के स्थल परिवर्तन की खबर से गीदम के व्यापारी वर्ग एवं गीदम के आम नागरिक निराश एवं आक्रोशित हैं। गीदम नगर के समस्त जन मेडिकल कॉलेज के गीदम के अलावा अन्य किसी स्थल में खुलने के विरोध में हैं। जिस पर विधायक चैतराम अटामी ने व्यापारी संघ को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही स्थल चयन कर लिया जाएगा और स्थल परिवर्तन नही किया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने व्यापारियों के हितार्थ किए जाने वाले कार्यो के बारे मे व अन्य समस्याओं से विधायक चैतराम अटामी को अवगत करवाया जिसमे मेडिकल कॉलेज का स्थल परिवर्तन न हो वह गीदम ब्लाक में ही बने, केंद्रीय विद्यालय में सीट की बढ़ोतरी हो जिससे कि अधिक बच्चो को विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल सके, जिले के सभी हाट बाजरो में पीने का स्वच्छ पानी, छोटे बड़े

सभी व्यापारियों के लिए बाजार शेड, बाजार स्थल पर सीसी सड़क, टॉयलेट बाथरूम, बाजार स्थल में सूखे पेड़ व ऐसे पेड़ जिनकी डाल आदि गिरने से दुर्घटना घट सकती है उनकी कटाई अथवा छटाई, गीदम में मुर्गा मार्केट के लिए उचित स्थल का चयन हो व अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। व्यापारियों की सभी समस्याओं को विधायक ने ध्यान पूर्वक सुना एवं आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं को शीघ्र ही दूर किया जायेगा। इस बैठक व्यापारी संघ परिवार के वरिष्ठ व्यवसाई किशन लाल, जगन्नाथ गुप्ता, गजानंद निर्मलकर, पुतान कुशवाह, भानु देवांगन को विधायक चैतराम अटामी ने शॉल श्रीफल देकर व्यापार के माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नगर की सेवा व समर्पण के लिए सम्मानित किया। चैतराम अटामी ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ग को मेहनत करने की शिक्षा व्यापारियों से सीखनी चाहिए। व्यापारी जितना परिश्रम करता है व अपने काम के प्रति जितना समर्पित होता है। उतना मेहनत समर्पण जो भी करे उसे सफल व सम्पन्न होने से कोई नही रोक सकता। चैतराम अटामी ने साप्ताहिक बाजारों में पीने के पानी की व्यवस्था बाजार स्थल पर टॉयलेट बाथरूम व बाजार शेड उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक चैतराम अटामी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी सदस्य व पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनीष सुराना, पुतान कुशवाह, अनिल जॉर्ज, मल्लिकार्जुन राव व व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं समस्त व्यापारी उपस्थित रहे।

महिला माओवादियों की भूमिका भी खतरनाक

कांकेर। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांकेर के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी बात ये है कि मारे गए इन 29 नक्सलियों में से 15 महिला नक्सली शामिल हैं।

हाल के दिनों में महिला नक्सलियों की भूमिका बढ़ी है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला नक्सलियों ने ही दंतेवाड़ा और बीजापुर की मुठभेड़ में बलिदान हुए सुरक्षाबलों के जवानों से हथियार एकत्र करके उनके पार्थिव शरीर को क्षतविक्षत करते देखी गई थीं।

कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जो करीब 4 घंटे तक चली। डीआरजी और बीएसएफ की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर 29 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 15 महिलाएं और 14 पुरुष थे। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। वहीं माओवादियों के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है।

मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया था। बताया जाता है कि मारा गया खूंखार नक्सली शंकर राव पर 25 लाख रुपये का इनाम था। वहीं मारी गई महिला नक्सलियों में दो महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख का इनाम था। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीवीसी रैंक के लीडर थे।

नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे जवान

बीएसएफ और डीआरजी की टीमों द्वारा 16 अप्रैल को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। तभी माओवादी की तरफ से गोलीबारी हुई और बीएसएफ सैनिकों ने उनके खिलाफ प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की। बता दें कि छत्तीसगढ़ दूसरा सबसे नक्सली प्रभावित राज्य है। गृह मंत्रालय के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं।

कांकेर में कब-कब मुठभेड़

16 अप्रैल से पहले कांकेर में 25 फरवरी को नक्सली एनकाउंटर में तीन नक्सली मारे गए थे। तीन मार्च को हिदूर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। जबकि एक बस्तर फाइटर का जवान बलिदान हुआ था। वहीं 16 मार्च को भी मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था।

बीएसएफ और डीआरजी ने मिलकर चलाया अभियान

छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ बीएसएफ की विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर बीएसएफ और डीआरजी द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली क्योंकि सैनिकों ने शीर्ष नक्सली कमांडर शंकर राव सहित 29 नक्सलियों को मार गिराया। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। सफल ऑपरेशन से नक्सलियों की रीढ़ तोड़ने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में सामान्य स्थिति और विकास लाने के प्रयासों में काफी वृद्धि होगी।

कांकेर में एंटी-नक्सल ऑपरेशन पर बीएसएफ के डीआइजी वीएम बाला का कहना है कि बीएसएफ पुलिस की मदद के लिए यहां आई थी। यह बहुत अच्छा ऑपरेशन था। हमारी दोनों टीमों, डीआरजी और बीएसएफ ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। घायल बीएसएफ कर्मी खतरे से बाहर है और रायपुर में इलाज चल रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

चुनाव प्रशिक्षण में न आने पर 15 कर्मचारियों को नोटिस

धमतरी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारी जोर-शोर के साथ चल रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी धमतरी, कुरूद और सिहवा विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारियों को 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल नही होने वाले करीब 15 कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वही जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नही देने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि लोकसभा, विधानसभा या अन्य निर्वाचन को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी जिले के बड़े से लेकर छोटे अधिकारी कर्मचारियों की रहती है। इसके लिए चुनाव से पहले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर बताया जाता है कि मतदान के दिन की प्रक्रिया सहित चुनाव के दिन कैसे काम करना है। इसके साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसका निपटारा कैसे करना है, इसकी जानकारी भी दी जाती है।

निर्वाचन कार्य हेतु श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी का संपूर्ण परिसर अधिग्रहित

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू कार्य संपादन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामग्री वितरण/वापसी एवं मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम तथा आवश्यकतानुसार निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के संपादन हेतु श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी के संपूर्ण परिसर का अधिग्रहण निर्वाचन कार्य समाप्ति अवधि तक के लिए किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी के आदेशानुसार उक्त महाविद्यालय परिसर को निर्वाचन कार्य के लिए संबंधित कार्य विभाग को सुव्यवस्थित आरक्षित रखने एवं भारसाधक अधिकारी का नाम तथा कार्यालय परिसर की चाबी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्वाचन कार्य हेतु किसी भी समय इसकी आवश्यकता पडने पर इनका उपयोग किया जा सकता है।

अनावेदक के खिलाफ कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा अनावेदक दिलीप उडिया आ. स्व. गंधर्व उडिया उम्र-41 वर्ष साकिन-रूप नगर उडिया पारा, कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला-दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। ज्ञात हो कि अनावेदक दिलीप उडिया थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध की गयी है। अनावेदक वर्ष 2011 से निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगति में रहकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हुये अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया। अनावेदक 06 मार्च 2013, 04 दिसंबर 2011, 04 नवंबर 2013, 14 मार्च 2014, 02 नवंबर 2014, 08 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 23 सितंबर 2015, 12 अक्टूबर 2015, 18 सितंबर 2017, 02 अगस्त 2018 एवं 27 अगस्त 2018 को विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया।

85+ आयु वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग 18 व 19 अप्रैल को

राजनांदगांव। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले में होम वोटिंग के लिए 17 मतदान दल का गठन किया है। गठित मतदान दलों द्वारा प्रारूप 12 घ में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले 85+ आयु वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के घर पर जाकर 18 एवं 19 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होम वोटिंग कराई जाएगी। प्रत्येक दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस कर्मी एवं वीडियोग्राफर होंगे। होम वोटिंग के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ के लिए 6 मतदान दल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव के लिए 7 मतदान दल गठित किए गए है, वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी के लिए 2-2 मतदान दल गठित किए गए हैं।

बस्तर की मंहगी वनोपज चिरौंजी की खरीदी ठप

जगदलपुर। बस्तर के जंगलों में इन दिनों चार के पेड़ फल से लदे हुए हैं। चार फल से निकलने वाले बीज को चिरौंजी कहा जाता है, और बाजार में 1000 से 1200 रूपए प्रतिकिलो के भाव से बिकता है। लेकिन ग्रामीण चिरौंजी के बजाय चार गुठली को ही व्यापारियों के पास औने-पौने दाम पर विक्रय करते हैं। हालांकि वन विभाग भी समर्थन मूल्य घोषित कर चिरौंजी गुठली की खरीदी करता है, पर इसके पहले ही कोचिया गांवों में पहुंचकर खरीदी कर लेते हैं। इससे ग्रामीणों को चिरौंजी गुठली की सही दाम नहीं मिल पाते है। औषधीय गुणों से भरपूर चिरौंजी का उपयोग मेवा के रुप में होता है। इन दिनों बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में ग्रामीण महिलाएं चार पाक को दोनी में बिक रहीं है, और प्रति दोनी 20 रूपए में बिकता है। वहीं चार के कच्चे फल को तोड़ने के बाद उसे सूखा लेते हैं, और सूखा चार फल को व्यापारी खरीदी करने घर तक पहुंचते हैं। बस्तर में कभी ग्रामीण नमक के बदले चिरौंजी देते थे।

बालको में हादसे के बाद चक्काजाम, दो एफआईआर दर्ज

पुलिस ने जुर्म दर्ज कर पहचान की कार्रवाई शुरू की

कोरबा। बालको के परसाभाठा मार्ग में नवधा पंडाल के पास हुए हादसे में ऑटो चालक की मौत के मामले में चक्काजाम करने व शव को सडक़ पर रखकर प्रदर्शन को लेकर दो अलग-अलग अपराध दर्ज किया गया है। एक शिकायत में कहा गया है कि 14 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे कुछ अज्ञात 5-10 लोगों ने परसाभाठा मेन रोड में शव को रखकर नारेबाजी, अपशब्द बोल कर एवं आने -जाने वाले लोगों से विवाद किया गया। अज्ञात शव का इस प्रकार अपमान रोड में करना जो आने-जाने की सडक़ है जिस पर सैकडों वाहनों एवं लोगों व पशुओं का आवागमन होता है गंदगी रहती है उस पर अज्ञात शव को रखकर शव का अपमान किया गया जिससे मानवीय भावनाओं को क्षति पहुंची है। बालको पुलिस ने धारा 279,34 के तहत अज्ञात के बिरुद्ध जुर्म दर्ज किया है। इसी तरह वाहन चालक नीलांबर की रिपोर्ट पर 40-50 व्यक्तियों पर धारा 294, 34, 341 आईपीसी का जुर्म दर्ज किया गया है। आरोप है कि 13 अप्रैल को एक्सीडेंट की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्व परसाभाठा बजरंग चौक पास चक्का

जाम किये थे। प्रार्थी अपना कैम्पर वाहन लेकर बालको से कैम्प आर.के.टी.सी. की ओर जा रहा था। परसाभाठा के पास 40-50 असामाजिक तत्वों के द्वारा एक्सीडेंट की घटना को मुद्दा बनाकर चक्काजाम कर रास्ता बंद कर आवागमन 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक अवरूद्ध किया गया था। जो भी ड्रायवर जाम में फंसे थे उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौच किया गया। बिना किसी कारण के आने जाने वाले लोगों का रास्ता जबरदस्ती रोका बाधा उत्पन्न की गई जिससे हमें मानसिक और आर्थिक परेशानियां हुई है।13 अप्रैल को जाम लगने के कारण लगभग हजारों गाडियां प्रभावित हुई, जिसके कारण कई ड्राइवरों की तबियत गर्मी अत्यधिक होने से खराब हो गई थी। 40-50 असामाजिक तत्व चक्काजाम कर अपने लाभ का अवसर बनाते है और अपने निजी स्वार्थ के कारण हजारों गाड़ी मालिक एवं ड्राइवरों को परेशान करते है, इन असामाजिक तत्वों को इसकी कोई भी चिंता नहीं होती कि जाम के कारण ड्राइवर एवं गाड़ी मालिक को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होती है और लगभग सभी गाड़ी मालिक अपने गाडियो का किश्त भी जमा करते है। जाम के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है, ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर पहचान की कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्साह के साथ मनाई गई रामनवमी

मनेन्द्रगढ़। राम जन्मोत्सव और रामनवमी के मौके पर बुधवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रामनवमी पर्व मनाया गया। इस दौरान श्रीराम मंदिर, श्रीहनुमान मंदिर, दुर्गा धाम आदि में राम जन्मोत्सव मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु जमा होने लगे थे जैसे ही दोपहर के 12:00 बजे समूचा मंदिर परिसर भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। भगवान के पट खुलते ही सभी ने भगवान की नयनाभिराम झांकी के दर्शन किये। इसके अलावा चैती नवरात्र के नौवें दिन श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान जिले में कई स्थानों में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया।

श्रीराम के जयकारे से क्षेत्र का माहौल गुंजायमान होता रहा। वहीं केसरिया वस्त्र के साथ युवा वर्ग व श्रद्धालु पूर्णतया भक्ति भाव लीन रहे। जगह जगह हो रहे भक्ति जागरण, रामचरित मानस पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, अष्टयाम संकीर्तन आदि धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन के बीच बुधवार को शांति व सौहार्द के वातावरण में रामनवमी पर्व सम्पन्न हुआ। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में व्यवसायियों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की साफ सफाई तो कई दिन पूर्व से ही शुरू थी।

संक्षिप्त समाचार

मतदान के दिन इन संस्थानों में काम करने वाले लोगों को मिलेगी छुट्टी

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के तहत् लोकसभा निर्वाचन के लिए नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन की ओर से सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र बस्तर में 19 अप्रैल, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में 26 अप्रैल और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 7 मई को मतदान होना है। इसी प्रकार पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार-व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित और कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन को 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मतदाताओं को जागरूक करने नगर निगम ने दिया बोट पर वोट का संदेश

रायपुर। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में ज़िला प्रशासन द्वारा आम मतदाताओं को 7 मई को मतदान का संदेश देने संचालित अभियान के तहत नगर निगम कमिश्नर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जोन -4 की टीम ने कैनोइंग क्लब के साथ बूढ़ातालाब विवेकानंद सरोवर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया । तैराकों ने अपने साथ बोट में मतदान संदेश के प्ले कार्ड्स के साथ अपने करतब भी दिखाए। इस दौरान जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा , सहायक अभियंता पद्माकर श्रीवास ने मॉर्निंग वॉक पर निकले नागरिकों को मतदान शपथ दिलाई। अद्भुत प्रदर्शन को देखने इस दौरान कई नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्री के बैग से मिला 10 लाख कैश

रायपुर। आरपीएफ की टीम को गाड़ी संख्या

12069 जनशताब्दी एक्स्प्रेस से उतरे यात्रियों की जांच के दौरान कोच संख्या सी-03 से उतर कर बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को सीढ़ी के पास रोका गया नाम पता पूछने पर जितेंद्र बोरकर पिता अशोक बोरकर उम्र 40 वर्ष निवासी चंदन आवास 4/50 राजकिशोर नगर बिलासपुर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ने उसके पास रखे नीले रंग बैग के बारे में पूछने पर बैग में कैश होना बताया और कैश ?10,000,00 (दस लाख) होना बताया उक्त कैश ले जाने के संबंध में कागजात की मांग करने पर मौके पर कोई वैद्य कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त जानकारी अविलंब वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए उक्त व्यक्ति को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर लाया गया जहां उडन दस्ता विधानसभा रायपुर उत्तर क्षेत्र के उडनदस्ता के कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीप्ति तिवारी को जानकारी दिया गया। उक्त सूचना पाकर उडनदस्ता टीम रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर में पहुंचकर उक्त कैश ?10,000,00 (दस लाख रुपये) को उपस्थित गवाहों के समक्ष गिनती कर मौके पर उडनदस्ता कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीप्ति तिवारी मेम द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर अपने कब्जे में लिया गया। ये कार्रवाई पोस्ट प्रभारी रायपुर के नेतृत्व में उप निरीक्षक केबी गुप्ता सहायक उप निरीक्षक डीके वर्मा प्रधान आरक्षक पी के मेश्राम प्रधान आरक्षक जेएल कौशल द्वारा की गई।

हम देश से उखाड़ फेंकेंगे नक्सलवाद, जारी रहेगी कार्रवाई : शाह

कांकेर मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने को केंद्रीय गृह मंत्री ने बताई सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता

कांकेर। कांकेर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बड़ी बात ये है कि 29 में से 15 महिला नक्सली शामिल हैं। इसी मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, उस अभियान को और गति मिली।

अमित शाह ने आगे कहा कि 2014 से हमने कैंप लगाना शुरू किया। 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद लगभग तीन महीने में 250 कैंप लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 80 नक्सली मारे गये हैं, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बहुत कम समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे।

वहीं कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जो करीब 4 घंटे तक चली। डीआरजी और बीएसएफ की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर 29 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 15

महिलाएं और 14 पुरुष थे। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। वहीं माओवादियों के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। दरअसल मंगलवार को कांकेर में पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सली मारे थे। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया था जिस पर 25 लाख का इनाम था। बताया जाता है कि मारा गया खूंखार नक्सली शंकर राव पर 25 लाख रुपये का इनाम था। वहीं मारी गई दो महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख का इनाम था। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीवीसी रैंक के लीडर थे।

भूपेश बघेल को जवानों से माफी मांगनी चाहिए : विजय शर्मा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नक्सलियों से मारे जाने की बात कबूली है। ऐसे में भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यजनक है। उनको अपने बयान पर जवानों से माफी मांगना चाहिए। अगर यह माफी नहीं मांगते हैं, तो जनता इसका जवाब देगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर मुठभेड़ पर जवानों को दी बधाई देते हुए कहा कि जवानों के समर्थन पर, जवानों के कंधों के ताकत पर, कल जो कुछ हुआ है, वह बड़ी सफलता है। आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए जवानों को मैं बधाई देता हूं। नक्सलियों के मांद में घुसकर नक्सलियों में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा किया है।

वहीं नक्सलियों के साथ बाहरी ताकतों के शामिल होने पर विजय शर्मा ने कहा कि मतलब यह है कि इंसास मिलता है, एके 47 मिलता है, तो यह क्या है, कहां से आ रहा है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें हमारे ही कुछ लोग मिलकर के इस तरह के काम करेंगे तो नहीं चलता है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि देश में जनता मरते रहे और देश के विकास को कोई बाधा करके बैठ रहे और उसका समर्थन करते रहे।

भूपेश बघेल ने 'फर्जी मुठभेड़' पर दी सफाई

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षाबलों के द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना को 'फर्जी' बताए जाने वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इसके साथ उन्होंने इसे सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसके लिए जवानों को बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व घटित नक्सल घटना को लेकर दिए गए मेरे बयान को अभी की घटना से जोड़ कर बताया गया है। भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, यह बेहद दुर्गभाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि मैंने फर्जी मुठभेड़ की बात पूर्व घटित घटना के विषय में कहा था, जिसमें ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए थे। अभी 29 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों से मार गिराया है, यह बड़ी कामयाबी है। मैं इस सफलता के लिए बधाई देता हूं।

अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जताया संदेह

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान के बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा अगर सच है तो बड़ी उपलब्धि है, यदि निर्दोष ग्रामीण हैं, तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सत्य सामने आना चाहिए। सच में नक्सली हैं, कही निर्दोष ग्रामीण तो नहीं।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर में नक्सली मुठभेड़ में बाहरी ताक़तों का हाथ होने पर कहा कि बाहरी ताक़त है, तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार की नीयत साफ़ नहीं है। साय सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। सरकार अलग बात करती है, और अधिकारी अलग। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर दीपक बैज ने कहा कि वे जो कहते है सोच समझ कर कहते हैं। कोई जानकारी होगी, इस बात पर इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ महीने में फर्जी मुठभेड़ कर ग्रामीणों को मारा गया है, जिस पर सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ये पूरे 29 नक्सली है। चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी मुठभेड़ के संयोग पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने संदेह जताया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

बस्तर सीट पर भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप वोट मांगने पहुंचे डोर टू डोर

बीजापुर। बस्तर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, बस्तर के दिग्गज नेता केदार कश्यप और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया।

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भी भाजपा का प्रचार भोपालपटनम ब्लॉक में थमा हुआ था। जिसके बाद मंगलवार को भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भोपालपटनम का रुख किया। नगर में पहली बार आए महेश कश्यप, मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कार्यकर्ताओं ने हेलीपेड पर जोरदार स्वागत किया। अपने प्रत्याशी को देख कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए।

भोपालपटनम ब्लॉक में प्रचार में आए महेश कश्यप ने सबसे पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। मंदिर से फॉरेस्ट नाका

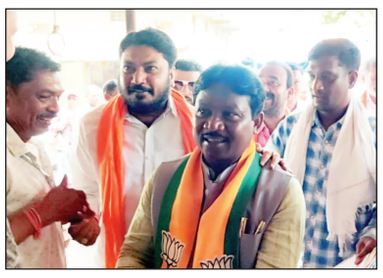

तक घर घर और बाजार पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। महेश कश्यप के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था। अब की बार 400 पार के नारे लेकर कार्यकर्ता घूम रहे थे।

बस्तर की लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपना दम लगा रहे हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने बस्तर में सभा की तो राहुल गांधी ने भी कवासी लखमा के लिए वोट मांगा।

चुनाव को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे नक्सली

■ मुठभेड़ पर सीएम साय बोले- यह ऐतिहासिक सफलता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांकेर में 29 नक्सलियों के एनकाउंटर पर कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को बधाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। सीएम हाउस में मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सली लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा लगता है कि नक्सली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। वो चुनाव बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिसे सीमा सुरक्षा बलों और पुलिस ने नाकाम कर दिया है।

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में 3 जवान जो घायल थे, उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है।

निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून-खराबे का यह खेल बंद हो। हम फिर से नक्सलियों से यह कहना चाहते हैं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें। विकास की मुख्यधारा में शामिल हों। उनके आतंक और हिंसा से कोई समाधान नहीं निकालने वाला। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है। बस्तर में तो दो दिन बाद ही चुनाव है। कल वहां चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियद नेल्लानार आदि योजनाओं के जरिये विकास सुनिश्चित करते हुए आलोकतांत्रिक हिंसा के विरुद्ध कड़ाई से निपटने के सिद्धांत के साथ ही इस समस्या के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिया जवानों का हाल-चाल

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात घायल जवानों को देखने नारायणा अस्पताल देवेंद्र नगर पहुंचे । जवानों का हाल-चाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज की तारीख याद रखी जाएगी, जब हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने कांकेर जिले के हापाटोला के जंगल में नक्सलियों की मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जबरदस्त मुठभेड़ में करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया। इसका पूरा श्रेय सुरक्षाबलों को जाता है, सभी को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह संभव हुआ है ।

छत्तीसगढ़ में जैसे गोबर खरीदी बंद हुई वैसे ही महादेव सट्टा एप बंद करे भाजपा: भूपेश बघेल

कवर्धा। राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बोलते हैं कि कांग्रेस हर महिला को एक लाख रुपये सालाना देने की बात कह रही है लेकिन कांग्रेस के पास तो फंड ही नहीं है, वह इतना पैसा कहां से लाएगी। जबकि सरकार का बजट ही 45 करोड़ का है। भूपेश ने कहा कि भाजपा के नेताओं को देश के सरकार का बजट भी नहीं मालूम, सरकार का बजट 47 लाख करोड़ रुपये का है।

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि भाजपा के लोग गली-गली में भूपेश बघेल पर गोबर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। अगर हमने घोटाला किया है तो सत्ता उनके हाथ में है, घोटाले की जांच कराएं और दोषी को सजा दें।

भाजपा के लोग कांग्रेस सरकार में शराब घोटाला, चावल घोटाला, महादेव सट्टा एप, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, अब जब सत्ता भाजपा के हाथ में है तो जैसे गोबर खरीदी बंद कर दी, वैसे ही शराब और महादेव सट्टा को बंद क्यों नहीं किया।

वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि यह भारत में संभव ही नहीं है। भाजपा जनता का ध्यान भटकाने दुनिया भर की उटपटांग बात करती है, ताकि लोग उलझे रहे। एक बार में नगरपालिका से लेकर लोकसभा तक चुनाव अगर एक साथ होता है और यदि नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी या कोई सरकार दो साल में गिर जाती है तो क्या दोबारा चुनाव करने उन्हें तीन साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक क्या राष्ट्रपति कानून लगा रहेगा, ऐसा संभव ही नही है।

भूपेश बघेल ने फिर से ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाया। बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हमने नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया। बैलेट पेपर से चुनाव ही सबसे आसान और निष्पक्ष तरीका है। चुनाव में अनपढ़ आदमी भी देखकर समझ सकता है। लेकिन ईवीएम मशीन को बड़े से बड़े पढ़े-लिखे लोग भी नहीं समझ पाते, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना ही सही है लेकिन भाजपा नहीं चाहती।

जांजगीर चांपा में कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी प्रत्याशी ने भरा नामांकन

जांजगीर चांपा। जिले में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन फार्म जमा करने का दौर जारी है। मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने अपना नामांकन फार्म जमा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। उसके बाद अपना नामांकन फार्म जमा करने कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन फार्म जमा कर दिया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है।

जांजगीर चाम्पा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के हित में होने का दावा किया। उन्होंने कहा 18 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया जायगा।

बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने मुहूर्त के अनुसार मंगलवार को अपना नामांकन फार्म जमा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 19 अप्रैल को एक सेट नामांकन फार्म फिर से जमा किया जायगा। उस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता नामांकन रैली में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने कहा क्षेत्र की जनता प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्य पर भरोसा जता रहे हैं। भले ही जांजगीर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक नहीं है, लेकिन इस बार मोदी और साय सरकार के कार्यों पर जनता मुहर लगाएगी।

जांजगीर चांपा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रोहित डहरिया अपने जीत का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के सांसदों को आड़े हाथ लिया और दोनों पार्टी के सांसदों पर क्षेत्र के विकास में किसी तरह का योगदान नहीं देने का आरोप लगाया। इस बार जांजगीर लोकसभा कि जनता ने बीएसपी को जीताने का मन बना लिया है।

रायपुर स्मार्ट सिटी ने खेल एवं युवा कल्याण को 95 रनों से हराया

रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नेताजी सुभाष स्टेडियम में लोकसभा निर्वाचन 2024 के स्वीप कार्यक्रम के तहत 16 अप्रैल को अंतर विभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य खेला गया। इस सेमीफाइनल मुकाबले में रायपुर स्मार्ट सिटी ने 205 रन विशाल स्कोर बनाकर जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दूसरा सेमीफाइनल में अब नगर निगम का मुकाबला पुलिस विभाग से गुरुवार की शाम को होगा। फाइनल शनिवार होगा ।

खेले गए मैच में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम टॉस जीतकर प्रबंध संचालक श्री अबिनाश मिश्रा के नेतृत्व में पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बल्लेबाज मुकेश की 103 रन और आकाश के 82रनों की आतिशी पारी से पूरी टीम 205 रन का लक्ष्य दिया। खेल एवं युवा कल्याण की टीम ने इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए 110 रन बना सकी। ऑल राउंड प्रदर्शन करने वाले 4 विकेट और 103 बनाने वाले मुकेश मैन ऑफ द मैच रहे।

इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में मतदाताओं को अपने बहुमूल्य मतदान देने के लिए नगर निगम आयुक्त श्री अविनाश मिश्रा ने मतदाताओं को शपथ दिलाई एवं इस मैच में स्वीप के जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्व दीप सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई नेत्रियों ने की प्रेस वार्ता

■ कहा- कांग्रेस की घोषणाएं महिलाओं के साथ भद्दा मजाक, हमें केवल वोट बैंक के तौर पर किया जाता है इस्तेमाल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं नेत्रियों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस का दमन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव, नगरपालिका अध्यक्ष महासमुंद अनिता रावटे, जगदलपुर महापौर सफीरा साहू और महासमुंद की जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा पटेल और अरुणा शुक्ला ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पत्रकार वार्ता में नेत्रियों ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन कराने और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गम्भीरता से लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और वादा किया था कि प्रत्येक थाने में एक महिला सेल स्थापित किया जाएगा जिसमें महिला अपराधों से सम्बन्धित स्वतंत्र जांच की जाएगी। लेकिन

कांग्रेस के पूरे पांच साल के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अनाचार, दुर्व्यवहार और हिंसा होती रही और कांग्रेस की सरकार आंखे मूंदे बैठी रही, कांग्रेस के नेता जुमलेबाजी और अवांछनीय बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस की सरकार ने है हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 4 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी कुल 20 सिलेंडर दिए जाने थे लेकिन किसी को कुछ नही मिला।

बस्तर प्रवास पर आईं बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया है। राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में गंगा मैया की सौगंध खाकर महिलाओं से धोखा किया था। कांग्रेस में महिलाएं घुटन महसूस कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार में कई योजनाएं महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संचालित की जा रही हैं। कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। भाजपा नेत्रियों ने कहा कि कदम-कदम पर महिलाओं के साथ छल और विश्वासघात कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। महिलाओं के लिए जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया और जो 500 रु महिलाओ को नहीं दे पाए आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे है कांग्रेस एक बार फिर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, पर वादा पूरा नहीं हुआ। शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने वाली कांग्रेस की सरकार ने उसमें दो हजार करोड़ रुपए का घोटाला तक कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि महतारी सम्मान योजना के तहत प्रति माह 500 रुपए और विधवा और वृद्ध महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन 5 साल में एक रुपए तक महिलाओं को नहीं दिया गया।

महिला आयोग की पूर्व सदस्य अनिता रावटे ने महिला स्व सहायता समूहों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ करने वादा किया था। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सख्त नियम बनाने भी कहा था। लेकिन कर्ज माफ करना तो दूर, रेडी टू ईट योजना का काम भी छीन कर महिला स्व सहायता समूह की बहनों को रातोंरात बेरोजगार बना दिया।

जगदलपुर महापौर सफीरा साहू ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अपमान करते हैं। जबकि भाजपा में महिलाओं को न केवल योजनाओं में बल्कि संगठन में भी सम्मानित किया है। हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से जब महिलाओं के अपमान के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये गलत बातें हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उनकी अपनी विचारधारा है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान होता है।

आदर्श लोकतंत्र के तकाजे का रखें ध्यान

अश्वनी कुमार

देश में आम चुनावों के दौरान प्रमुख विपक्षी नेताओं की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारियां भारत के लोकतंत्र की गर्वित पहचान तो नहीं हो सकती। इन गिरफ्तारियों के पीछे केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोप चिंताजनक हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्ता विरोधियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जांच एजेंसियों का पक्षपाती रवैया, नागरिकों के मूलभूत मानवीय अधिकारों का हनन और संवैधानिक संस्थाओं की उदासीनता से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। दार्शनिकों का यह मानना है और इतिहास की गवाही भी कि अनर्गल राजनीतिक व प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग ऐतिहासिक सच्चाई है जिसकी पुष्टि समय-समय पर, हम अपने देश में देख चुके हैं। सरकारें चाहे किसी भी दल की हों। वर्तमान में महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि राज्यों में भी सत्ताधारी पार्टियों ने राजनीतिक विरोधियों पर कानूनी शिकंजा कसने के प्रयास किए हैं। नौकरशाही पर अपने व्यापक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप पहले इतने तीखे न थे। जिनसे न्याय की अपेक्षा है, वही आज कठघरे में हैं। बिना आरोप सिद्ध हुए पीएमएलए जैसे कठोर कानून के तहत लंबे समय तक आरोपियों को हिरासत में रखना लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतावादी संविधान के दर्शन के अनुरूप तो नहीं है। यद्यपि कानून की नजर में सभी समान हैं और राजनीतिक नेताओं से उच्च आदर्शों एवं कानून का पालन करने की अपेक्षा है। देश में ऐसी भावना नहीं बननी चाहिए कि प्रमुख विपक्षी नेताओं पर अपराध के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। खासतौर पर जब देश की न्याय प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ी सजा है और सदा न्याय संगत नहीं होती। इस प्रक्रिया में न केवल आरोपी पिसता है, परंतु उसके समस्त परिवार का कई तरह से उत्पीड़न होता है, यहां तक कि बच्चों पर भी तंज कसे जाते हैं। आरोपी अपने आपको शून्य महसूस करने लगता है और टूट जाता है। क्या यह आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कीमत हो सकते हैं? कानूनी दांवपेंच बेगुनाहों को भी अपराधी साबित कर देते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वकील एफली बेली अपनी किताब 'द डिफेंस नेवर रेस्ट्स' में लिखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया की चक्की में जब पिसाई होती है तो अभियुक्त की बेगुनाही अप्रासंगिक हो जाती है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय (गंगाबाई बनाम संभाजी, 2008), में दोहराते हुए, कानूनी प्रक्रिया के भंवर में न्याय की हत्या से सचेत किया है। देशवासियों की अपेक्षा है कि पीएमएलए जैसे कठोर कानून के प्रावधानों का पालन करना, संविधान के अनुच्छेद 21, जो प्रत्येक व्यक्ति की आजादी एवं सम्मान के अधिकार को मान्यता देता है, की मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा के भीतर होनी चाहिए। राजनीतिकों के विरुद्ध प्रत्येक मुकदमा मीडिया ट्रायल का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण जांच से लेकर अदालत के अंतिम निर्णय तक आरोपी के सम्मान एवं आजादी का हनन होता रहता है। राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक मर्यादा, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया एवं राष्ट्रीय गरिमा के बीच अभिन्न संबंध है। इनका तकाजा है कि हर व्यक्ति को कानून के मुताबिक सौम्य न्याय मिले। यही एक आदर्श लोकतंत्र की पहचान है। इतिहास साक्षी है कि अन्याय का एहसास सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बनता है। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों को स्वीकार करना होगा कि विरोधियों के प्रति अभद्र भाषा और अत्याचारिक रवैया कभी न मिटने वाली व्यक्तिगत शत्रुता और चुभन को जन्म देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित करते हैं। आज देश में तनाव का वातावरण है, जिसकी जवाबदेही किसी एक दल अथवा व्यक्ति की नहीं. कुछ नेता, जो आज अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उन्होंने भी अतीत में राजनीतिक मर्यादाओं को नहीं निभाया।

राजनीतिक दलों का चुनावी ऑफर

अनिल तिवारी

लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दावों और वादों का पिटारा खुल गया है। जितने उम्मीदवार, उतने वादे। जितने दल, उतने दावे। इन वादों और दावों की अंधी गलियों में आम आदमी खो सा गया है। राजनीतिक दलों की ओर से घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा चालू है। कोई घी दूध की नदियां बहाने का सपना परोस रहा है, तो कोई पलक झपकते चांद सूरज मुट्ठी में कर लेने का पासा फेंक रहा है। संख्या बल के हिसाब से जो दल न तीन में है न तेरह में वे तो घोषणाओं के मामले में स्थापित दलों से कई गज आगे कूद रहे हैं। मिनटों में हथेली पर सरसों उगा लेने जैसे असंख्य नुस्खों के साथ वे जनता को भरमाने में जुटे हुए हैं।

आप चाहे मोदी की गारंटी कहें, न्याय पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, विजन डॉक्यूमेंट कहें या फिर घोषणापत्र, बात एक ही है कि किसी तरह जनता को सपनों की दुनिया में ले जाकर उनके कीमती वोटों की फसल काटना। इस सपनीली दुनिया की माया भी है, और राम भी। गेहूं भी है, और गुलाब भी। निर्भर जनता पर करता है कि उसकी रुचि किसमें है, लौकिक जीवन के सुख में, या पारलौकिक दुनिया में सब कुछ पा लेने की उम्मीद भरे संतोष में। बहरहाल, 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के नये घोषणापत्र पर आम और खास सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र का नाम न्याय पत्र दिया है। इसके नाम के पीछे तर्क है, न्याय पत्र आम लोगों को न्याय दिलाएगा। कांग्रेस के न्याय पत्र में पांच न्याय और 25 गारंटी हैं। पांच न्याय हैं- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय।

कांग्रेस के घोषणापत्र में सभी वर्गों के लिए रेवड़ियां हैं। इसमें 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी को प्रति दिन 400 रुपये किया जाना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाना और पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाना शामिल हैं।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के न्याय पत्र के जवाब में सत्ताधारी दल भाजपा ने भी मोदी की गारंटी शीर्षक से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 सामाजिक समूहों के लिए वादों पर खूब जोर है। यह समूह है गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक, किसान, मछुआरे, मजदूर, व्यापारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे पारंपरिक रूप से वंचित वर्ग। मोदी की गारंटी में 70 साल के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य योजना, थर्ड जेंडर को भी आयुष्मान में शामिल करना, वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, ओलंपिक की मेजबानी के साथ-साथ इंसान को चांद पर भेजने का वादा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है लेकिन राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) जैसे विवादास्पद मुद्दे से परहेज रखा है। 76 पृष्ठों के इस घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के 24 अध्याय हैं जिसमें विकास के लिए चुनिंदा क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है।

इस क्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार शीर्षक से अपना घोषणापत्र विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही गई है, जिसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। 2025 तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पेपर लीक से मुक्ति दिलाने और किसान को सभी फसल पर एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाने की बात भी कही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपने घोषणापत्र में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करने का वादा किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का भी वादा किया गया है। यह भी कहा है कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये की जाएगी। भाकपा ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खात्मे, आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने, जाति जनगणना कराने, संपत्ति कर व विरासत कर जैसे कराधान उपाय लागू करने, कॉरपोरेट कर बढ़ाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का भी वादा किया है। मोटे तौर पर राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कार्यक्रम, नीतियों तथा उद्देश्यों को बताने के लिए घोषणापत्र जारी करते है। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में घोषणापत्र एक तरह से राजनीतिक दलों के कार्यों का आईना होता है। इसके माध्यम से दलों की नीतियों का पता चलता है। जनता को यह जानने का पूरा हक है कि जिस प्रतिनिधि को वह अपना बहुमूल्य वोट देने जा रही है, वह क्या करना चाहता है, उसकी नीतियां क्या हैं।

मौजूदा चुनाव के लिए विभिन्न दलों की ओर से आ रही गारंटी फेस्टिवल ऑफर का एहसास कर रही हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की 25 गारंटी। ये गारंटी सही मायने में फेस्टिवल ऑफर की तरह हैं। मतलब लोकतंत्र के महोत्सव में राजनीतिक दलों का फेस्टिवल ऑफर। बाजारवाद का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। वोट दो और ये ऑफर (गारंटी) ले जाओ। जनता के वोट 24 कैरेट सोने की तरह हैं, लेकिन गारंटी कितनी पक्की हैं, यह वक्त बताएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के संकल्प पत्र के 10 मुख्य बिंदुओं में शामिल थे- अयोध्या में राम मन्दिर, जम्मू-कश्मीर से धारा 35ए और 370 हटाना, छोटे किसानों के लिए पेंशन, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन, राष्ट्र सुरक्षा पर वादा, एक साथ चुनाव कराने का संकल्प, प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, आयुष्मान भारत योजना, समान नागरिक संहिता और ट्रांसजेंडर्स को समाज को मुख्य धारा में लाने का वादा।

भाजपा ने अयोध्या में राममन्दिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से धारा 35ए और 370 हटाने, आयुष्मान भारत योजना जैसे वादों को पूरा किया है लेकिन, प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन, छोटे किसानों के लिए पेंशन किसानों की दो गुनी आय, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार अभी भी दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। यहां यह कहना गलत न होगा कि दस साल के शासनकाल में भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए संकल्पित दिखी। कई एक वादों पर भाजपा ने गंभीरता से काम किया है। समान नागरिक संहिता की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। वादे के अनुरूप भाजपा के काम करने का उत्साह सहज ही देखा जा सकता है।

कांग्रेस भी विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में सत्ता में आई, वहां घोषणापत्र को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत दिखी। 2014 से कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से दूर है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आती है, तो अपने घोषणापत्र को जमीन पर उतारने में सफल रहती, या उसके सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। अब देखना है कि 2024 लोक सभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। कौन-सा गठबंधन केंद्र की सत्ता तक पहुंचता है, और अपने घोषणापत्र में किए गए दावे और वादों के अनुरूप जनता को सशक्त करने के लिए काम करता है। फिलहाल राजनीतिक सौदागर सपना बेचने में जुटे हुए हैं। गारंटी के जाल में कौन फंसता हैए इसका अंतिम निर्णय 4 जून को ही होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-59)

गतांक से आगे...

प्रार्थना के द्वारा किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दु:ख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बन्धनस्वरूपा जानो। महात्माजन सत-असत्रूप समस्त पदार्थों की इच्छा-आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्णरूपेण परित्याग करके परमउदार पद को प्राप्त करते हैं।

बन्धन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख-दु:ख स्वरूपा सत् एवं असत् की आस्था-विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशान्त महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ। हे महात्मन् ! पुरुष के चार तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता-पिता के संयोग से हुई है। हे ब्रह्मन्! अब द्वितीय निश्चय सुनें। बन्धन में दु:खों का अवलोकन कर मैं सभी तरह के जागतिक प्रपञ्चों-विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अतिसूक्ष्म आत्मा हूँ। यह निश्चय ज्ञानीजनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। हे विप्रवर! तृतीय निश्चय यह है कि मैं सम्पूर्ण चराचर जगत् के पदार्थों की आत्मा हूँ, सर्वरूप एवं क्षयरहित हूँ इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का विशेष कारण होता है।

बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्तृता एवं अन्दर से अकर्तृता बने रहकर शुद्धभाव से जगत् में सर्वत्र रमण करो। अहं को त्यागकर शान्त चित्त हो, कलङ्क रूपी कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध-परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक में विचरण करो। उदार एवं उत्तम आचरण से सम्पन्न, सभी श्रेष्ठ आचार-विचारों का अनुगमन करते हुए अन्दर से आसक्ति-रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे।

क्रमश: ...

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका

अभिषेक अग्निहोत्री

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जब भी जिक्र होगा, एक महायोद्धा तात्या टोपे की चर्चा सर्वोपरि होगी। इस संग्राम में अंग्रेजों ने बड़े-बड़े राजाओं को हरा दिया था, लेकिन इस महायोद्धा के शौर्य, रणकौशल, चातुर्य और संगठन क्षमता को अंग्रेज कभी पराभूत नहीं कर सके। आजीवन वे अंग्रेजों को छकाते रहे, नई-नई सेनाएं लेकर हमला करते रहे। उनके जीवन का अंत उनके अभिन्न रहे राजा मानसिंह के विश्वासघात से हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें सोते हुए धर दबोचा और सूली पर चढ़ा दिया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई थी। 161 साल पहले फांसी का फंदा खुद अपने गले में डालने वाले इस योद्धा की शौर्यगाथा अपने आप में अद्वितीय है।

तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित येवला गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव द्वितीय के कर्मचारियों में से थे।

विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। जल्द ही क्रांति की चिन्गारी समूचे उत्तर भारत में फैल गयी। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोडने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्तरंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब, बहादुरशाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब एक साल बाद तक तात्या विद्रोहियों की कमान संभाले रहे।

सन् 1857 के संग्राम की लपटें जब कानपुर पहुंचीं तो सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की सेना ने कानपुर पर हमला किया। तब तात्या बहादुरी से लड़े, परंतु 16 जुलाई, 1857 को उनकी पराजय हुई और उन्हें कानपुर छोडना पड़ा। तात्या ने दोबारा सैनिक ताकत जुटाकर बिठूर को केंद्र बनाया। इस बीच हैवलॉक ने फिर हमलाकर उनकी सेना को पराजित किया। तात्या ने यहां से निकलकर ग्वालियर कंटिजेंट रेजीमेंट को अपनी ओर मिलाया और नवंबर 1857 में कानपुर पर हमला किया। इस तीव्र आक्रमण से ब्रिटिश सेना के पांव उखड़ गए, लेकिन इस क्षणिक विजय के बाद 06 दिसंबर को ब्रिटिश सेना ने तात्या को पराजित कर दिया। तात्या ने खारी पहुंचकर फिर सेना और तोपें जुटाईं और 22 मार्च को करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मी बाई की मदद को पहुंच गए। यहां अंग्रेज सेना हारी, लेकिन कालपी में फिर तात्या को हार का मुंह देखना पड़ा। वे ग्वालियर चले गए और महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को मिलाकर फिर ब्रिटिश सेना पर हमला किया और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया। यहां झांसी की रानी, तात्या और राव साहब ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। मगर ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने फिर हमला किया और फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून, 1858 को शहीद हो गयीं।

इजरायल पर हमले का आर्टिकल 51 से कनेक्शन

अभिनय आकाश

देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और दुनिया में इस वक्त हलचल मची है। ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। कहा जा रहा है कि ये उस हमले की जवाबी कार्रवाई है जो दो हफ्ते पहले इजरायल की तरफ से की गई थी। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। हवाई हमले में दूतावास की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ईरान के सात बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान का आरोप है कि ये हमला इजरायल ने किया। सीरिया इजरायल के बॉर्डर पर है। सीरिया के जरिए ईरान हिज्बुल्ला को हथियार भेजता है।

इजरायल का ऐसा आरोप रहा है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक रिव्यल्यूशनरी गार्ड वहां से कॉर्डिनेट करते हैं। इसलिए वो वहां अलग अलग ठिकानों पर हमले करता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया। उसके बाद से इजरायली हमलों का संख्या सीरिया और इराक में बढ़ी है। तब ईरान की तरफ से धमकी दी जाती थी कि हम बदला लेंगे। उसने डॉयरेक्ट इजरायली भूमि पर आज तक हमला नहीं किया। 1948 में अरब इजरायल वॉर हुआ और फिर 1956 में स्वेज नहर संकट, 1967 में सिक्स डे वॉर, 1973 का युद्ध लेकिन ईरान कभी इन युद्धों में किसी की तरफ से शामिल नहीं हुआ। 1979 तक तो इजरायल और ईरान दोस्त हुआ करते थे। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए।

इजरायल पर ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियों गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वैनेस फ्रेजियर को पत्र लिखा, जिसमें ईरान ने इजरायल पर हमला करने के पीछे संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया और इसे अपना वैध अधिकार बताया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता

है, तो वर्तमान चार्टर में अंतर्निहित व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार को नष्ट नहीं करेगा, जब कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती।

अब इजरायल की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। इजरायल के रिएक्शन पर ही वेस्ट एशिया और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स निर्भर करेगी। पश्चिम एशिया में और अशांति भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन तेहरान और जेरूसलम के मुकाबले में भारत कहां खड़ा है? नई दिल्ली के लिए क्या दांव पर है।

इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर ईरान ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एमएससी एरीज़ नामक एक कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। इज़रायली-संबद्ध जहाज में चालक दल के 17 भारतीय सदस्य हैं और यह मुंबई में न्हावा शेवा बंदरगाह की ओर जा रहा था। रूष्ट एरीज़ अब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नियंत्रण में है। भारतीय दल की सुरक्षा भारत के लिए बड़ी चिंता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अमीर अब्दुल्लाहियन से बातचीत की है और इस मुद्दे को उठाया है। तेहरान ने जारी किया है कि भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही एमएससी एरीज़ के भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीराब्दुल्लाहियन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि तेहरान जल्द ही भारत सरकार के अधिकारियों को मालवाहक जहाज एमएससी एरीज़ पर सवार 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा, जिसे ईरानी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जब्त कर लिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ फोन पर एमएससी एरीज़ पर 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और इस संबंध में तेहरान से सहायता का अनुरोध किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इज़राइल में भारत का लगभग 97,467 बड़ा प्रवासी है। देश में 18,000 से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनमें से कई देखभालकर्ता और कृषि श्रमिक हैं। अधिक भारतीयों के यात्रा करने की उम्मीद है क्योंकि दोनों देशों ने निर्माण श्रमिकों के रूप में नियोजित करने के लिए 1,500 नागरिकों को यहूदी राष्ट्र में ले जाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2 अप्रैल को पहला जत्था भेजा था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में आने तक दूसरा जत्था नहीं भेजने का फैसला किया है।

भारत किसी का पक्ष नहीं ले सकता और उसे एक बार फिर कूटनीतिक राह पर चलने की जरूरत है। नई दिल्ली के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। ईरान एक पुराना साझेदार है और दोनों ने वर्षों से अपने संबंध बनाए रखे हैं। तेहरान भारत के कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है लेकिन यह पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय सामानों को भूमि पारगमन की अनुमति नहीं देता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान का व्यवहार और काबुल में सरकार नई दिल्ली और तेहरान दोनों को चिंतित करती है। भारत के इज़राइल के साथ रणनीतिक संबंध भी हैं, खासकर जब रक्षा और सुरक्षा की बात आती है। नई दिल्ली देश से सैन्य उपकरणों का शीर्ष खरीदार है और इज़राइल ने गोला-बारूद प्रदान करके कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया था। भारत-इज़राइल व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं और व्यापार लगभग 7.5 बिलियन डॉलर का है। भारत और इज़राइल दोनों की आतंकवाद के बारे में समान चिंताएँ हैं, जिन्हें 26/11 के हमलों के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।

पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश अपना 80 प्रतिशत कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। वृद्धि की स्थिति में, पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है और इससे कीमतों में वृद्धि होगी। यदि कीमतें लंबी अवधि तक ऊंची रहती हैं, तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि मुद्रास्फीति नीचे की ओर जा रही है और चालू खाता घाटा प्रबंधनीय है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने मनीकंट्रोल के हवाले से कहा कि अर्थव्यवस्था कुछ समय तक इसे झेलने में सक्षम रहेगी। हालाँकि, अगर यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका असर मुद्रास्फीति और चालू खाते दोनों पर पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी और मौद्रिक सहजता में देरी हो सकती है। भारत की प्रमुख अरब देशों, ईरान और इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी है। पश्चिम एशिया में इसके हित अब तेल आयात और श्रम निर्यात तक ही सीमित नहीं हैं। अरब देश भारत के आर्थिक और राजनीतिक साझेदार हैं और एक व्यापक संघर्ष उन्हें इसमें शामिल कर सकता है। भारत अस्थिर क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ काम कर रहा है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर जोर दे रहा है। इससे नई दिल्ली को रणनीतिक और आर्थिक लाभ होगा। लेकिन संभावित व्यापक संघर्ष भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

आज का इतिहास

1848 पंजाब में दूसरा आंग्ल-सिख युद्ध समाप्त किया गया।
1859 वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को फांसी दी गयी।
1880 विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में बेंजामिन डिजरायली धरा को हरा कर दोबारा प्रधानमंत्री।
1899 फौर्निसेउर महारानी विक्टोरिया द्वारा एक रॉयल चार्टर सेंट एंड्रयू एम्बुलेंस एसोसिएशन का गठन किया गया।
1906 सेन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत।
1906 एक बड़ा भूकंप और जिसके परिणामस्वरूप आग ने सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया (क्षति का चित्रण), कम से कम 3,000 लोगों की मौत और शहर की आबादी के बेघर होने की अधिक संभावना को छोड़कर।
1923 मेजर लीग बेसबॉल के न्यूयॉर्क यांकीज़ ने नवनिर्मित यांकी स्टेडियम में खेल खेलना शुरू किया।
1938 सुपरमैन, जेरी सिएगेल और जो शस्टर द्वारा बनाई गई, एक्शन कॉमिक्स 1 में पहली सच्ची सुपरहीरो कॉमिक बुक में अपनी शुरुआत की।
1947 सबसे बड़े गैर-परमाणु एकल विस्फोटक डेटोनेशन इतिहास में, रॉयल नेवी ने हेलिगोलैंड, जर्मनी के द्वीप को नष्ट करने के असफल प्रयास के साथ 4,000 टन अधिशेष गोला बारूद स्थापित किया।
1949 आयरलैंड ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया और वे रिपब्लिक बन गए।
1952 पश्चिमी जर्मनी और जापान ने राजनयिक संबंध स्थापित किये।
1955 महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ।
1958 विवादास्पद अमेरिकी कवि एजरा पाउंड को वाशिंगटन डी.सी. के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल से रिहा कर दिया गया था, जहां उन्हें बारह साल तक कैद रखा गया था।
1971 वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में सुनील गावस्कर ने 220 रन बनाए। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए थे।
1983 1983 में बेरूत के संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास पर बमबारी से 63 लोग मारे गए।
1994 वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकार्ड बनाया।
1994 ब्यूटी एंड द बीस्ट को न्यूयॉर्क शहर के पैलेस थिएटर में रिलीज़ किया गया था।
1994 98 वाँ बोस्टन मैराथन केन्या के कोस्मस नडेती ने जीता था। उन्होंने सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट 15 सेकंड में मैराथन पूरी की।
1994 ब्रायन लारा ने तिहरा शतक बनाया। उन्होंने एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन बनाए।

इस्लामिक देशों के एजेंडे पर चल रहा संयुक्त राष्ट्र?

संजय तिवारी

संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) ने 15 मार्च को ऐतिहासिक पहल करते हुए दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यूएन में सिर्फ प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ बल्कि दुनियाभर के देशों से कहा गया है कि वो अपने यहां ऐसे कानून बनाये जिससे इस्लाम की बेहूरमती न होने पाये। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस प्रस्ताव को आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज (ओआईसी) की ओर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था जिसके समर्थन में 115 देशों ने मतदान किया। इनमें चीन, रूस और अमेरिका भी शामिल हैं। 44 देशों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें भारत सहित यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं।

इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत श्रीमती रुचिरा कम्बोज ने भारत के इस मतदान से दूर रहने की वजह बताते हुए कहा कि यह समय है जब हमें रिलिजिसफोबिया की ओर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एक धर्म की बात करें। उन्होंने दुनिया के 1.2 अरब हिन्दुओं, 50 करोड़ बौद्धों और 2 करोड़ सिखों की बात करते हुए कहा कि हमें उनके भी मानवाधिकारों की बात करनी चाहिए जिनके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है और उनका उत्पीड़न होता है। असल में संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया को लेकर जो प्रस्ताव आया है वह प्रस्ताव ही भेदभावपूर्ण है। इसमें एक धर्म के खिलाफ लोगों की बढ़ती नफरत पर चिंता तो व्यक्त की गयी है लेकिन अन्य धर्मों के खिलाफ जो नफरत है उसकी अनदेखी कर दी गयी है। यूएन द्वारा जारी प्रेस रिपोर्ट में ईसाई और यहूदी का एक लाइन में जिक्र तो है लेकिन दुनिया के तीसरे बड़े धर्म हिन्दू का जिक्र अन्य के रूप में किया गया है।

जबकि जिस पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया है, उस पाकिस्तान में हिन्दुओं, ईसाइयों को नरकीय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नागरिक अधिकारों का ऐसा भीषण भेदभाव है कि कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान के शीर्ष पदों पर संवैधानिक रूप से बैठ ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रस्ताव के यूएन में पास होने से ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि उसका बुनियादी चरित्र बदलकर ओआईसी वाला हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में पिछले साल से इस्लामोफोबिया के खिलाफ माहौल बनना शुरु हुआ और इस साल प्रस्ताव पास करके दुनियाभर के देशों को इसे रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कह दिया गया। अब इसके लिए पर्याप्त धन और प्रभाव का इस्तेमाल भविष्य में किया जाएगा ताकि दुनिया के सभी गैर मुस्लिम देशों में ऐसे कानून बन जाएं ताकि वहां इस्लाम की सच्चाई बताने, या फिर इस्लामिक हिंसा के बारे में जानकारी देने को अपराध माना जाए।

इस्लामिक देशों में ऐसा पहले से ही है। दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां इस्लाम की निंदा, आलोचना या उसके प्रतीकों पर सवाल उठाने को अपराध समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में तो इसके लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा तक का प्रावधान है। मतलब इस्लामिक देशों में रहते हुए आप किसी भी प्रकार से इस्लामिक सिद्धांतों, प्रतीकों पर सवाल नहीं उठा सकते। एक मनुष्य की सभी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी तब खत्म हो जाती है जब वह इस्लाम पर सवाल उठाना चाहता है। ओआईसी और अन्य इस्लामिक देश अब यही व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के जरिए संसार के सभी गैर इस्लामिक देशों में बनाना चाहते हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र में ओआईसी का प्रभाव इस सदी की शुरुआत में उस समय बढ़ना शुरु हुआ जब दुनियाभर में इस्लामिक आतंकवाद पैर पसार चुका था। इसी दौर में ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकल

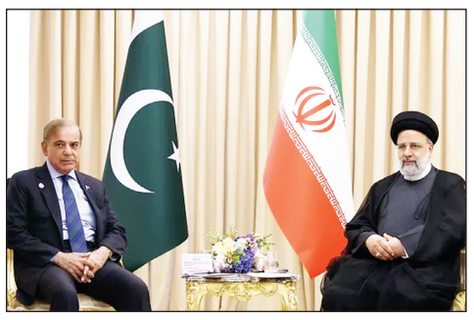

संसार में उभरते विरोधाभासों से निपटने में मदद की पेशकश की। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की इस पेशकश का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया। लेकिन अब लगभग 23-24 साल बाद वह सहयोग इस्लामोफोबिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और प्रयास के रूप में सामने आया है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रस्ताव को पेश किया गया था वह भी मेलजोल से विवादों को सुलझाने और सभी धर्मों का सम्मान करने जैसे उपदेशों से भरा हुआ था। लेकिन उस समय जिस काउण्टर टेररिज्म इंपलीमेन्टेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया था वह खत्म हो चुका है। स्वाभाविक है इस्लामिक देशों के संगठन के साथ तालमेल करके संयुक्त राष्ट्र ने जो पहल शुरु की थी, आखिरकार ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र को ही इस्लामिक देशों के संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस्लामिक देशों खासकर अरब देशों के पास पैसा है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हमेशा अपने दानदाताओं के प्रभाव में रहती हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधन खर्च करने की बात कर रहा है तो इसके पीछे अमीर अरब देशों का ही पैसा होगा। पाकिस्तान जैसे देश तो सिर्फ मुखौटा हैं जो आगे बढ़कर अपने आपको सच्चा इस्लामिक मुल्क साबित करना चाहते हैं। यह अरब देशों का ही पैसा और प्रभाव है कि संयुक्त राष्ट्र सभी प्रकार के मानवाधिकारों को किनारे करके इस्लामिक प्रतीकों की रक्षा करने में जुट गया है।

संयुक्त राष्ट्र के इस इस्लामीकरण में यूएन सेक्रेटरी जनरल एन्टोनियो गुन्टेरेस, उनकी डिपुटी अमीना मोहम्मद या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष वोल्कर तुर्क की तिकड़ी की भी अहम भूमिका है। वोल्कर तीन दशक से संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हैं और उनके कैरियर की शुरुआत ही कुवैत की फंडिंग से हुई थी। उनके वक्तव्य, बयान और प्रयास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के बजाय इस्लामिक अधिकारों के लिए लड़नेवाले किसी मौलाना की तरह होते हैं। यूरोप में जब से इस्लाम की सच्चाई बताने या कुरान जलाने की घटनाएं हुई हैं तब से इस तिकड़ी के इस्लामिक प्रतीकों की इज्जत करने तथा इस्लाम के प्रति सहिष्णुता बढाने वाले बयान आते रहते हैं। उन प्रयासों का यह चरम था कि सभी प्रकार के नागरिकों के मानवाधिकार किनारे करते हुए किसी इस्लामिक संगठन की तरह संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ न सिर्फ प्रस्ताव पारित कर दिया बल्कि हर साल 15 मार्च को इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी कर दिया। यह बिल्कुल वही तरीका है कि क्राईम करके अपने आप को विक्टिम घोषित कर दो। इससे लोग आपके क्राइम के बजाय आपके विक्टिम होने पर चर्चा शुरु कर देंगे।

संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो इस्लामिक देशों के संगठन की तरह व्यवहार करे। इस्लामिक सिद्धांत मेलजोल वाली सभ्यताओं में विश्वास नहीं करते इसलिए उन्होंने अपना अलग वैश्विक संगठन ओआईसी बना रखा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी अगर ओआईसी की भाषा बोलेगा तो दुनिया के उन देशों के लिए संकट पैदा होगा जो संयुक्त राष्ट्र को सर्वधर्म समभावी संगठन मानकर उससे जुड़े हुए हैं। इस्लामोफोबिया उन लोगों द्वारा गढा गया एक सिद्धांत है जो नहीं चाहते कि इस्लामिक सच्चाइयां सबके सामने आये। वरना अगर इनकी नीयत ठीक होती तो संसार के अलग अलग बौद्धिक और सामाजिक मंचों का इस्तेमाल करके वो यह साबित कर देते संसार के लोग इस्लाम के बारे में जैसा सोचते हैं, इस्लाम वैसा नहीं है। यह करने के बजाय इस्लामिक देशों का समूह और अब संयुक्त राष्ट्र भी गैर इस्लामिक देशों को भी उन इस्लामिक देशों की तरह बनाना चाहते हैं जहां इस्लाम की आलोचना या समीक्षा के लिए भी सरकारी सजा का प्रावधान है। अब संयुक्त राष्ट्र चाह रहा है संसार के सभी प्रकार के संचार माध्यमों से इस्लाम की आलोचना या समीक्षा पर रोक लगे। खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर ऐसे फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाए जो इस्लाम की आलोचना को खत्म करते हों। लेकिन खुद मुस्लिम समुदाय जो इस्लाम के अलावा बाकी हर धर्म को कुफ्र मानकर उसे समाप्त करने की वकालत करता है उसके ऊपर कोई चर्चा करने से संयुक्त राष्ट्र क्यों परहेज कर रहा है? क्या इस प्रकार से कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था अपनी विश्वसनीयता बचाकर रख पायेगी? यह तो अच्छा है संयुक्त राष्ट्र के इस भेदभावपूर्ण प्रस्ताव से भारत सहित संसार के 44 देशों ने अपने आपको अलग कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सामने यह सवाल हमेशा रहेगा कि धार्मिक भेदभाव की बजाय उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुद्दा क्यों उठाया? संसार के सभी गैर मुस्लिम देशों को दार-उल-हर्ब मानकर उसके खिलाफ जंग को जायज माननेवालों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? पूरी मानवता को काफिर और मोमिन में बांटनेवाली विचारधारा पर अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय उसे ही इस्लामोफोबिया का दोषी ठहरा देना कहां का मानवाधिकार है, जिसकी वकालत यूएन कर रहा है?

अप्रत्याशित संकटों से निपटने की तैयारी

डॉ. धनंजय

भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने उचित ही यह आह्वान किया है कि सशस्त्र सेनाओं को 'ब्लैक स्वान' यानी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि देशों के बीच की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में तकनीक एक नया क्षेत्र बनकर उभरा है।'ब्लैक स्वान' घटनाओं का तात्पर्य ऐसी घटनाओं से है, जो अचानक घटित हो, जो कल्पना से परे हो। आज के दौर में सुरक्षा के मायने केवल सीमा सुरक्षा की पारंपरिक समझ तक सीमित नहीं है। अब इसमें मानवीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि पहलू भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश की वित्तीय प्रणाली पर ऐसा कोई साइबर हमला हो, जो दो-तीन दिन के लिए अर्थव्यवस्था को ठप या बाधित कर दे। या स्टॉक एक्सचेंज में डिजिटल सेंधमारी हो जाए और शेयर बाजार रुक जाए। या विद्युत ग्रिड और उसकी आपूर्ति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश हो। ऐसे हमलों के बारे में सोचा नहीं जाता या उनकी आशंका का अनुमान नहीं होता, वे अप्रत्याशित होती हैं। एक और उदाहरण देखें- अमेरिका में हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अभी लाल सागर में जो संकट चल रहा है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति शृंखला पर पड़ रहा है। आज के समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषता है उसकी अंतर्निर्भरता और इंटरनेट से उसका गहरा संबंध। विभिन्न आपूर्ति शृंखलाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अगर एक जगह उसमें अवरोध आ जाए, तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ऐसे ही स्थितियों के लिए तैयार रहने की बात थल सेनाध्यक्ष जनरल पांडे ने की है। ऐसी घटनाओं को लेकर भारत ही नहीं, विश्व के तमाम बड़े देश आशंकित रहते हैं। उल्लेखनीय है कि ये खतरे केवल देशों की ओर से ही नहीं आते, नॉन-स्टेट एक्टर भी इस तरह की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। जैसे, हिंद महासागर क्षेत्र में कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाए, तो भारत के आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि उस क्षेत्र से हम तेल का आयात करते हैं, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार है। ऐसा होना एक 'ब्लैक स्वान' घटना ही होगी क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा नहीं था और उससे हमें परेशानी हुई। जनरल पांडे ने आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा को लेकर भी कहा है।'ब्लैक स्वान' घटनाओं का तात्पर्य ऐसी घटनाओं से है, जो अचानक घटित हो, जो परिकल्पना से परे हो। आज के दौर में सुरक्षा के मायने केवल सीमा सुरक्षा की पारंपरिक समझ तक सीमित नहीं है। अब इसमें मानवीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि पहलू भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश की वित्तीय प्रणाली पर ऐसा कोई साइबर हमला हो, जो दो-तीन दिन के लिए अर्थव्यवस्था को ठप या बाधित कर दे।

राष्ट्रपति पुतिन और परमाणु युद्ध की पहेली

मारूफ रजा

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में उनकी कार्रवाई को चुनौती दी गई, तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि रूस के पास सबसे बड़ा शस्त्रागार है, जो दुनिया को कई बार बर्बाद कर सकता है। इससे अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश चौंक गए। हालांकि वे जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जल्दबाजी में करने की संभावना नहीं है।

ये हथियार अंतिम उपाय हैं। हालांकि पुतिन अपने ब्रीफकेस (संचार उपकरण, जिससे पुतिन अपने सभी शीर्ष सैन्य कमांडरों से बात कर सकते हैं) साथ लेकर चलते हैं, पर वह जानते हैं कि एक बार जब परमाणु हमला शुरू हो गया, तो फिर पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब अमेरिकी नेतृत्व में नाटो का सैन्य हमला रूस के अस्तित्व के लिए खतरा हो। चूंकि पश्चिमी देशों ने रूस के विफल हमलों को देखा है, वे रूसी सैनिकों और संसाधनों को समाप्त करने के लिए गुप्त रूप से यूक्रेन को हथियार और सैनिकों की आपूर्ति करने की रणनीति जारी रखेंगे और तब तक युद्ध को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि कीव का पतन न हो जाए।

पुतिन की यह धमकी तब आई है, जब कुछ ही दिनों में उन्हें अगले छह साल के लिए नया कार्यकाल मिलने वाला है। पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा कि नाटो समर्थित यूक्रेन के जवाबी हमलों से कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों सहित रूस की क्षेत्रीय अखंडता के लिए यदि जरूरी हुआ, तो रूस अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। इसके अलावा, उन्होंने रूस के सुरक्षा सिद्धांतों और कानूनों का हवाला दिया, जो उन्हें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कोई भी रूसी नेता सांविधानिक रूप से उनके नतीजों को पलटने में सक्षम नहीं होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस के पास %परमाणु सुरक्षा के लिए एक सिद्धांत है, जो कि एक खुला दस्तावेज है।

एक इंटरव्यू में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह मानते हैं कि पुतिन झांसा नहीं दे रहे हैं। वह पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं। ये उनके परमाणु ब्लैकमेल का पहला कदम है। उनसे जब यह पूछा गया कि जब तक पुतिन सत्ता में हैं, क्या उन्हें यूरोप में स्थिरता दिख रही है, तो उनका स्पष्ट जवाब था-नहीं। मेरे पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। मेरी राय है कि नहीं। हमने वर्षों से इसे देखा है। हमें स्थिरता दिखाई नहीं देती। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, रूस सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार का दावा करता है, जिसमें करीब 6,000 परमाणु हथियार हैं। उनमें से करीब 1,500 अभी तैनात हैं।

आखिर पुतिन यह जोखिम क्यों ले रहे हैं? दरअसल, त्वरित सैन्य लाभ की उम्मीद में पुतिन ने खुद जनता का ध्यान शुरुआती कुछ महीनों में युद्ध की तरफ न जाने देने को प्रोत्साहित किया था। लेकिन अब उनके आक्रमण को रोक दिया गया है, जिससे रूस में असंतोष फैल गया है और इसलिए उन्होंने अपने देशवासियों के गिरते मनोबल को बढ़ाने के लिए अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। जब दो वर्ष पहले 2022 में रूसी सैनिकों ने कुछ बढ़त हासिल की थी, तो उन्होंने लामबंदी का आदेश दिया था, लेकिन वह जानते थे कि इससे समाज में गंभीर असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने आंशिक लामबंदी का आदेश दिया।

टिप्पणीकार एनी अप्पलबाम ने अटलांटिक में लिखा, सेना के भीतर समस्या है। और इसलिए रूसी सेना न केवल साजो-सामान संबंधी आपातकाल या रणनीतिक समस्या से जूझ रही है, बल्कि उसके मनोबल में भी गिरावट आ रही है। इसी वजह से पुतिन को और अधिक सैनिकों की आवश्यकता है और इसलिए, जैसा कि स्टालिन के समय में था, रूस ने अब स्वैच्छिक आत्मसमर्पण को अपराध घोषित कर दिया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों ने अग्रिम पंक्ति छोड़ दी है। एप्पलबाम आगे कहती हैं, पुतिन के लिए देश, विदेश और सेना में समर्थन खत्म हो रहा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा, वह इस गिरावट को रोकने के अलावा कुछ नहीं था।

विश्लेषकों का कहना है कि क्रेमलिन की परमाणु धमकी यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की एक चाल है। राजनीतिक विश्लेषक तातियाना स्टैनोवाया ने वर्ष 2022 में कहा था, %यह रूस की ओर से यूक्रेन और पश्चिम के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है = या तो यूक्रेन पीछे हट जाएगा या परमाणु युद्ध होगा।%

यह स्पष्ट नहीं है कि इस लामबंदी का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3,00,000 लोगों को प्रशिक्षित करने, उन्हें हथियारबंद करने और मोर्चे पर भेजने की चुनौती बहुत बड़ी थी, खासकर तब, जब रूस ने पहले ही अपने सबसे अनुभवी सैनिकों को तैनात कर दिया था। फिर भी, रूस ने यूक्रेन में सैन्य नुकसान की कुछ दुर्लभ स्वीकारोक्ति की। स्टैनोवाया ने कहा, सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से, लगभग कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, रूसी परमाणु हमले का जवाब पारंपरिक सैन्य या कूटनीतिक तरीके से देना और यूक्रेन को अधिक शक्तिशाली हथियार प्रदान करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ताकि वह रूस पर हमला कर सके। रूसी लामबंदी रूसी शहरों में विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है। यह यूरोप में इस बात को लेकर भी मतभेद पैदा कर रही है कि क्या बड़ी संख्या में युद्ध से भागे रूसी पुरुषों का स्वागत किया जाना चाहिए या उन्हें भगा देना चाहिए। यूक्रेनी और रूसी सैन्य योजनाकारों के लिए लड़ाई को और अधिक जटिल बनाने की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि यह एक पेचीदा सवाल है, लेकिन नाटो और अमेरिका किसी अंतर्निहित परमाणु खतरे के लिए तैयार नहीं दिखना चाहते हैं। विकल्प कठिन हैं, और पश्चिम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह रणनीतिक परमाणु हमले पर कैसी प्रतिक्रिया देगा।

इजरायल पर ईरानी हमले का क्या होगा अंजाम

रहीस सिंह

बीते शनिवार की देर रात ईरान ने इस्राइल पर 300 से अधिक मिसाइलें और किलर ड्रोन दागे। ईरान के इस हमले ने मध्य-पूर्व में पहले से चले आ रहे युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया, जिसके प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। वैसे यह संभावित था क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन तैयार हो गई थी, जब दमिश्क में ईरानी कॉन्स्युलेट पर हवाई हमला हुआ था। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई ने इस्राइल को दंडित करने की बात कही थी।

ईरान और इस्राइल लंबे समय से एक-दूसरे के विरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब यह प्रॉक्सी नहीं रह गया। हमले के बाद ईरानी सैन्य प्रमुख मेजर जनरल बाघेरी ने इस्राइल और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि यदि जवाबी कार्रवाई की गई तो अंजाम कहीं बुरा होगा। उधर, इस्राइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। यदि ऐसा हुआ तो केवल मध्य-पूर्व ही नहीं, संभव है पूरी दुनिया एक नए 'वॉर जोन' में दाखिल हो जाए।

ईरान और इस्राइल की दुश्मनी ऐसे तो खत्म नहीं हो पाएगी। इस्राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है, 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सिद्धांत है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे।' यह बात भी गौर करने लायक है कि इस्राइल इस हमले के लिए तैयार था। अमेरिकी खुफिया तंत्र के हवाले से ब्लूमबर्ग ने पहले ही बता दिया था कि ईरान, इस्राइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन से हमला कर सकता है। परिणाम यह हुआ कि इस्राइल ने बहुस्तरीय वायु-रक्षा प्रणाली से 90% हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन अगर दोनों तरफ से हमले बढ़ते हैं तो इस स्तर की सुरक्षा संभव नहीं हो पाएगी।

कुछ विश्लेषक ईरान को सचेत कर रहे थे कि यदि उसने इस्राइल पर मिसाइल या ड्रोन हमला किया तो यह उसके लिए जोखिम भरा होगा। फिर भी उसने हमला किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसने निर्णायक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रखी है? दरअसल,

ईरान लंबे समय से इस्राइल की तरफ से लड़े जा रहे एक छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। वह केवल यहूदी धरती पर ही छद्म युद्ध नहीं लड़ रहा बल्कि एक और युद्ध लड़ रहा है, जिसके लिए मजबूत सैन्य एवं रक्षा तंत्र की जरूरत है। इस्लामी दुनिया शिया बहुल और सुन्नी बहुल में बंटी हुई है। पश्चिमी जगत पहले के साथ खड़ी दिख रही है।

जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया तो उसे सुन्नी बम कह गया। जवाब में ईरान भी 'शिया बम' बनाना चाहता था। वह उसके करीब पहुंच भी गया था लेकिन जुलाई 2015 में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रूस और अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर इस पर अल्पविराम लगा दिया। 2018 में अमेरिका के इससे बाहर होने की घोषणा ने उसे एक और मौका दे दिया। उसके बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की जो सीमा करार में 3.67% तय की गई थी, उसे तोड़कर 2021 की शुरुआत में वह 20% तक चला गया था। यही नहीं, धीरे-धीरे वह 90% तक संवर्धन करने लगा, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है।

इसे देखते हुए ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रफाएल मैरियानो ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा और क्षमता बढ़ रही है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि ईरान ने परमाणु क्षमता विकसित कर ली हो और अब फिजिकल रेस्पॉन्स के लिए भी तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के रुख की वजह तो समझना चाहते हैं, पर उससे उलझने से बच रहे हैं?

दूसरा पहलू ईरान के जटिल सैन्य तंत्र का है। उसके पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़े आकार वाली सेना है। इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज के अनुसार, ईरान सशस्त्र बल में 5,80,000 एक्टिव जवान हैं। इसके साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर में विभक्त लगभग 2,00,000 प्रशिक्षित जवान सुरक्षित रखे गए हैं। ये जमीन, वायु और समुद्र में एक्टिव हैं। उसका कुद्स बल मध्य-पूर्व में लड़ाकू गुटों के एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। यह ईरान का रीजनल कोऑपरेटिव फोर्स है, जो उसके लिए प्रतिबद्ध होकर लड़ता है। यही नहीं, ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, स्पीडबोट और पनडुब्बियों के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है।

बहरहाल, यह युद्ध जारी रहा तो न केवल भू-राजनीतिक समीकरणों को बदलेगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है ईरान होरमुज जलडमरूमध्य को बाधित करे। ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। दुनिया में तेल की कुल खपत का लगभग 25% इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसका भारत सहित दूसरे देशों पर गहरा असर हो सकता है। भारत के दोनों ही देशों से कारोबारी रिश्ते हैं। बीते वर्ष भारत का दोनों देशों के साथ करीब 1.1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है।

ईरान और इस्राइल बीच संघर्ष इस समय 'ग्रे जोन' में है, जहां अभी कुछ भी साफ नहीं दिख पा रहा है। परंतु संकेत कुछ ऐसे हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने की मन:स्थिति में नहीं है। यानी अभी की स्थिति को देखते हुए माना जा सकता है कि इस्राइल पर ईरानी हमला एक शुरुआत भर है।

मालदीव की राह पर नेपाल

केएस तोमर

विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में कहा गया है कि विषम परिस्थितियां ऐसे लोगों को भी साथ आने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं होता। या यह कहें कि धुर विरोधी भी मिल जाते हैं। राजनीति में विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही है। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने राजनीतिक विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन से 15 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हिमालयी देश में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम ने भले ही प्रचंड की कुर्सी बचा ली हो, लेकिन यह भारत के लिए शुभ नहीं है। मालदीव में चीन समर्थक सरकार और पाकिस्तान से दुश्मनी के बीच नेपाल में चीन के प्रति वफादार कम्युनिस्टों के प्रभुत्व वाली नई सरकार का गठन इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने वाला है। विदेशी राजनीति के जानकारों के अनुसार, प्रचंड सत्ता में बने रहने की कला जानते हैं। नेशनल एसेंबली में नेपाली कांग्रेस के 89 और सीपीएन (यूएमएल) के 77 सांसद हैं, जबकि प्रचंड की पार्टी के सिर्फ 32 सांसद ही हैं। ओली की सीपीएन (यूएमएल) के सहयोग से प्रचंड वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री बने थे। दिसंबर, 2023 में ओली ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन प्रचंड नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने रहे। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रचंड का समर्थन करने से इन्कार कर दिया, जो उनके गठबंधन टूटने का मुख्य कारण बना था। अब नेपाली कांग्रेस के साथ गहरे मतभदों के चलते प्रचंड फिर से ओली के साथ आ गए हैं। हालांकि नेपाली कांग्रेस के साथ उभरे मतभेदों को सुलझाया जा सकता था। प्रचंड और देउबा ने मिलकर सात राज्यों में सरकारें बनाई थीं, अब उनका भविष्य भी खतरे में है। ओली के साथ आने और उनकी शर्तों की वजह से प्रचंड कमजोर पड़ गए हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रचंड पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। प्रचंड ने भी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रखने की अपनी बेबसी जाहिर की है। अब देखना होगा कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले दोनों प्रतिद्वंद्वी (प्रचंड और ओली) नए गठबंधन को कैसे संभालते हैं। भारतीय सेना ने 2022 में 40 हजार अग्निवीरों की भर्ती निकाली थी। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्पष्ट कर दिया था कि नेपाल सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो रिक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। अब नई सरकार के लिए इसे स्वीकार या अस्वीकार करना बड़ी चुनौती होगा। दरअसल अग्निवीर योजना का काठमांडु में कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने विरोध किया था। यह योजना 1947 में ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि से विनियमित है। लेकिन नेपाल का मानना है कि अग्निवीर योजना उस संधि का उल्लंघन है। अब ओली की पार्टी इसमें बाधा बन सकती है, क्योंकि उसका रुख चीन की ओर हो सकता है, जो भारत को मंजूर नहीं होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाली कांग्रेस का झुकाव भारत की ओर था, लेकिन प्रचंड और ओली के साथ आने से परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भारत को नेपाल संबंधी अपनी नीति में बदलाव करना होगा, ताकि नेपाल से रिश्ते सामान्य बने रहें। दूसरा, प्रचंड के नई दिल्ली दौरे के दौरान जो ऊर्जा समझौता हुआ, उसको लेकर भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। कई वर्षों के गतिरोध के बाद हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, भारत दस वर्षों के लिए नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा। इससे भारत को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा और हमारे देश को अतिरिक्त बिजली भी मिलेगी। नेपाल के इस नए घटनाक्रम को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। एक अन्य गंभीर मुद्दा है चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव। इस मामले में कोई भी प्रगति हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी 1,770 किलोमीटर सीमा खुली है। चीन ने नेपाल में 1.34 अरब डॉलर का निवेश किया है, वह इस योजना को लागू करने के लिए नई सरकार पर दबाव बनाएगा। नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान को भारत से दूर करने के चीनी प्रयासों से भारत को सतर्क रहने की जरूरत तो है ही, इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका से सहयोग की नीति पर फिर से काम करने की जरूरत है, क्योंकि चीन का बढ़ता प्रभाव हमारे हित में नहीं है।

ग्रेजुएशन के बाद छात्रों को अक्सर इस बात की चिंता सताने लगती है कि उच्च शिक्षा के लिए वो कौन सा कोर्स करें, जो उनके करियर को नई दिशा दे सके. लेकिन उन्हे ग्रेजुएशन के बाद होनेवाले कोर्सेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. लेकिन, अब छात्रों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीए, बीकॉम और बीएससी के बाद के कुछ हॉट कोर्सेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो करियर के चुनाव में मददगार साबित हो सकती है.

हॉट कोर्सेस

ये हैं वो हॉट कोर्सेस

ग्रेजुएशन के बाद देंगे आपके कैरियर को नई दिशा!

■ बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अनेक विकल्पों में से कोई कोर्स चुन सकते हैं या फिर सीधे किसी जॉब में लगकर अपने अनुभव और प्रतिभा के बल पर आगे जा सकते हैं.

■ दरअसल, बीएससी मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तक सीमित नहीं है. अनेक अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट्स में भी आप बीएससी करके अपने करियर की राह आसान कर सकते हैं.

■ अगर आप बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो भी यह जरूरी नहीं कि आप एमएससी ही करें. आप एमबीए करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एमसीए करके आईटी के क्षेत्र में या फिर बीएड करके एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं.

■ इसके अलावा यदि आप चाहें, तो कोई स्किल-बेस्ड शॉर्ट-टर्म टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे एसएपी, जावा, एसक्यूएल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बहरहाल ग्रेजुएशन के बाद अनेको हॉट कोर्सेस के विकल्प छात्रों के लिए खुले हैं. तो फिर देर किस बात की अब छात्र हॉट कोर्सेस में से अपना मनचाहा विकल्प चुनकर उसमें उच्च शिक्षा हांसिल कर सकते हैं.

बी ए के बाद क्या करें ?

■ आपने जिन विषयों में बीए ग्रेजुएशन किया है उनमें से किसी एक विषय में एमए कर सकते हैं. इसके अलावा बीएड, एमबीए, लॉ, हॉटेल मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे डिग्री कोर्सेस कर सकते हैं.

■ वहीं आप फिल्म मेकिंग, मास कम्यूनिकेशन, एनिमेशन, फैशन, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटीशियन, पीजीडीसीए जैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं.

■ बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन करके बेहतर करियर बनाया जा सकता है.

■ बीए करने के बाद एमए साइकोलॉजी कर साइकोलॉजिस्ट बना जा सकता है. मेडिकल और हेल्थ केयर क्षेत्र में साइकोलॉजिस्ट की बहुत मांग है.

■ फाइन आर्ट क्रिएटिव फिल्ड की चाहत रखने वाले युवा इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. पेंटिंग या स्कल्पचर्स में रुचि रखने वाले युवा इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं.

■ ऑर्कोलॉजी के कोर्स भी कई अच्छी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं. एम इन ऑर्कोलॉजी भी करियर का अच्छा विकल्प हो सकता है.

■ सिविल सर्विसेस, जर्नलिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, अनुवादक (हिंदी-इंग्लिश ट्रांसलेटर्स), लाइब्रेरी या फिर इंफोर्मेशन साइंस के कोर्सेस भी कर सकते हैं.

बी कॉम के बाद क्या करें ?

■ बीकॉम के बाद आपको वही कोर्स करना चाहिए जिसमें आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एमबीए करना चाहिए.

■ अगर स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो बीकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं.

■ बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम, एमफिल, पीएचडी कर लेते हैं और साथ ही नेट (ह्श्वङ्म) क्वालिफाई कर लेते हैं. तो आप बतौर लेक्चरर नियुक्त हो सकते हैं.

■ आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सीएस, सीए, आईसीडब्लूए, कॉस्ट एकाउंट जैसे कोर्सेस भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक पीओ, डिफेंस और रेल्वे में नौकरी के लिए भी एप्लाई कर सकते हैं.

■ कॉमर्स में युवा टैक्सेशन, कम्प्यूटर साइंस, फॉरेन ट्रेड, इंश्योरेंस, कम्प्यूटर अप्लीकेशन आदि में ग्रेजुएशन करने के बाद इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर शानदार करियर बना सकते हैं.

बी एससी के बाद क्या करें ?

कैरियर के रनवे पर दौड़ने से पहले...

पिछले वर्ष लेबर ब्यूरो सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 8.7 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जबकि उद्योगों की नजर में कोर्स कर निकलने वाले महज 25 प्रतिशत युवा ही रोजगार देने के काबिल हैं। यदि स्थिति तब है जब देश की एक बड़ी आबादी (करीब 60 करोड़) युवा है। क्षमता होने के बावजूद प्रोफेशनल्स का हुनर निखर कर सामने नहीं आ पा रहा है।

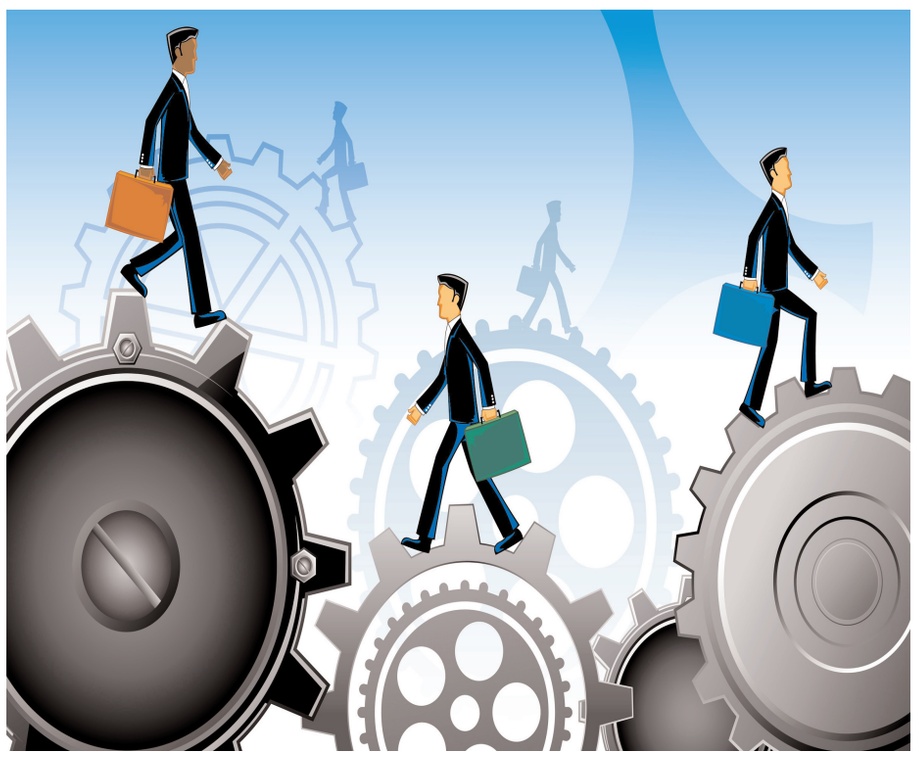

बहुत से युवा ग्रेजुएशन से पहले ही कोई भी नौकरी शुरु कर खुद को आत्मनिर्भर बना लेते हैं। ऐसी नौकरी भले ही उन्हें कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा दिलाती हों, मगर भविष्य में सिर्फ इसी के बूते तरक्की का सपना देखना बेमानी होगा।

पिछले वर्ष लेबर ब्यूरो सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 8.7 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जबकि उद्योगों की नजर में कोर्स कर निकलने वाले महज 25 प्रतिशत युवा ही रोजगार देने के काबिल हैं। यदि स्थिति तब है जब देश की एक बड़ी आबादी (करीब 60 करोड़) युवा है। क्षमता होने के बावजूद प्रोफेशनल्स का हुनर निखर कर सामने नहीं आ पा रहा है। अक्सर छात्रों की यही राय होती है कि ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, जबकि वास्तविकता तो यह है कि यदि छात्र ने गंभीरतापूर्वक ग्रेजुएशन की है और उसमें काबिलियत है तो उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश में सरकारी व निजी क्षेत्र की कई सेक्टर और इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बम्पर पैमाने पर ग्रेजुएट को जॉब दे रही हैं। यहां तक कि जॉब करते हुए भी प्रोफेशनल्स इनके बारे में सोच सकता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर एचआर हेड काम करने वाले सुमित अवस्थी का मानना है कि ग्रेजुएशन डिग्री लेकर जब कोई छात्र नौकरी तलाशता है या इस चक्कर में दूसरे शहर जाता है तो शुरू-शुरू में उसे कुछ परेशानी जरूर आती है, लेकिन यदि उसमें हौसला है तो वह ज्यादा दिन तक बेरोजगार नहीं रहेगा।

कुछ कोशिशें अपनी भी

ग्रेजुएशन के बाद नौकरी आसानी से मिल जाए या नौकरी के दौरान मोहभंग न हो, इसके लिए जरूरी है कि अपने स्तर से कोई चूक न करें। कोर्स के बाद अपने लिए नौकरी चुनते समय यह अच्छी तरीके से देख लें कि क्या जीवन में आपने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया है उस फॉर्मेट पर वह नौकरी है या नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की सीनियर फैकल्टी प्रो. अशुम गुप्ता का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी तो काफी जागरूक है। उसे अपने लिए अच्छा-बुरा सोचने की पर्याप्त क्षमता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने योग्य हैं? उस नौकरी के लिए जो-जो स्किल्स चाहिए, क्या आपके अंदर वो सब है। क्योंकि करियर की गाड़ी आपकी पसंद नहीं, बल्कि आपके स्किल्स से चलती है। यदि आप नौकरी के संबंध में पूरी तैयारी के साथ आते हैं तो काम के दौरान न सिर्फ आपको आनंद आएगा, बल्कि आगे बढ़ने के अवसर मौजूद रहेंगे।

इंटर्नशिप को हल्के में न लें

अक्सर छात्र इंटर्नशिप को महज एक सर्टिफिकेट तक सीमित मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि बतौर ट्रेनी छात्र इसे गंभीरता से लें तो उनके जॉब मिलने की कोशिश को ये काफी हद तक आसान बना देते हैं।

इंटर्नशिप का मौका मिलने पर नियमित रूप से उपस्थित रहें। हर एक काम को बारीकी से देखें और सीखने का प्रयास करें। यही आगे चलकर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल्स के रूप में स्थापित करेगा। सीखने के दौरान आपको जहां भी दिक्कत हो, तत्काल किसी सीनियर से पूछ लें, क्योंकि आप जिस संस्थान में इंटर्नशिप के लिए गए होंगे, वहां हर कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे, जो अपने काम में दक्ष होंगे। उनके अनुभव का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं।

नेटवर्किंग से पहुंचे मंजिल तक

करियर काउंसलर जितिन चावला के अनुसार नेटवर्किंग के सहारे जॉब मिलने की राह काफी आसान हो जाती है। यह नेटवर्किंग कई रूपों में बनती है। पढ़ाई के दौरान सीनियर से तालमेल बढ़िया हो, विजिटिंग फैकल्टी से बराबर संपर्क में रहें और इंटर्नशिप के दौरान वहां के लोगों के नाम और ईमेल आईडी लेकर आप अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। आजकल तो वॉटसएप और अन्य नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दूरियां काफी कम हो गई हैं। इंटर्नशिप के दौरान यदि आपने संस्थान के कुछ वरिष्ठ लोगों को प्रभावित कर लिया तो आपको नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। आपके क्षेत्र के जो भी महारथी हैं उनसे मेल-जोल बढ़ाएं। वे आपकी भरपूर मदद करेंगे।

रिज्यूमे हो दमदार

पहली नौकरी दिलाने में रिज्यूमें का अहम योगदान होता है। यह रिज्यूमे ही होता है, जो नियोक्ता को आपके बारे में सम्पूर्ण जानकारी देता है। कई बार हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि आज प्रजेंटेशन का जमाना है। जो जितना अच्छा दिखेगा वह उतना ही अधिक पसंद किया जाएगा। चरण-दर-चरण आगे बढ़ते हुए अब बात विजुअल रिज्यूमे की होने लगी है। रिज्यूमे तैयार करते समय आप अपने समस्त अनुभव और योग्यता के विवरण का उल्लेख करें। अपनी खूबियों और नापसंद को भी अपने रिज्यूमे में जगह दें। जो भी तथ्य उसमें डाल रहे हैं उससे पूरी तरह से वाकिफ रहें।

ऑनलाइन में करें लॉगइन

आज ऑनलाइन क्षेत्र में बंपर वैकेंसी हैं। कहीं आप प्रोग्रमिंग लैंग्वेज सीख पद प्रतिष्ठा सहित अच्छा वेतन पाते हैं, तो कहीं वेबसाइट्स से जुड़ सोशल मीडिया मैनेजर जैसे पदों पर पहुंच अपना हुनर दिखाते हैं। ऑनलाइन की दुनिया विशाल है। यहां आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग व निर्माण में अपना योगदान दे सकते सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ समय पहले लॉन्च किए गए नेशनल जॉब पोर्टल युवाओं के लिए रोजगार की तलाश पूरी कर सकता है। इससे राज्य सरकारें, परीक्षा कराने वाली संस्था, नौकरी के इच्छुक, जॉब बदलने वाले तथा नियोक्ता सभी जुड़ेंगे।

एयरलाइन्स इंडस्ट्री

– तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है एविएशन सेक्टर में भारत 2020 तक। युवाओं के लिए लाखों नए जॉब होंगे।

टेलीकॉम सेक्टर

■ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा टेलीकॉम सेक्टर में 2020 तक विभिन्न पदों के रूप में

फैशन इंडस्ट्री

■ 9.5 प्रतिशत की दर से ग्रोथ कर रहा है इंडियन डिजाइनर वियर मार्केट। 2020 तक इंडस्ट्री होगी 1000 करोड़।

आईटी सेक्टर

■ 03 करोड़ होगी आईटी इंडस्ट्री में 2020 तक कर्मचारियों की संख्या। देश की आईटी इंडस्ट्री होगी 225 बिलियन यूएस डॉलर।

हेल्थकेयर सेक्टर

■ 04 करोड़ को मिल सकता है हेल्थकेयर सेक्टर में प्रोफेशनल्स को रोजगार 2020 तक।

फैशन डिज़ाइनर स्टाइलिश कैरियर

दुनिया को अपनी डिज़ाइंस में देखना चाहते हैं और अपनी अलग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो ट्राई करें इस इंडस्ट्री को. बेहद ग्लैमराइज़ और स्टाइलिश इस फील्ड की दुनिया कायल है. नेम-फेम के साथ इसमें पैसा भी बहुत है. अपने करियर को एक अलग अंदाज़ देना चाहते हैं, तो इस फील्ड में बनाएं करियर. कैसे? आइए, हम बताते हैं.

शैक्षणिक योग्यता

इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बारहवीं पास होना ज़रूरी होता है. आप अगर बारहवीं पास हैं, तो इस क्षेत्र में आपके लिए सुनहरा अवसर है. इसके बाद किसी भी संस्थान से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं.

कोर्स के दौरान

सबसे अच्छी बात ये है कि बाकी कोर्सेस की तरह इसमें आपको पूरा समय नहीं देना पड़ता. आप अपनी सुविधानुसार क्लास का समय चुन सकते हैं. कोर्स के दौरान आपको गार्मेंट मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फैब्रिक पैटर्न मेकिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड आदि के बारे में पढ़ाया जाता है.

व्यक्तिगत विशेषता

भीड़ में भी सबसे अलग नज़र आनेवाला ये क्षेत्र उन्हीं लोगों के लिए अब तक सफल साबित हुआ है, जिनका इसके प्रति लगाव हो. कलर्स, फैब्रिक लेटेस्ट स्टाइल के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है.

कहां हैं जॉब?

इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है. अपनी क्षमता और पहुंच के हिसाब से आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं. शुरुआत आप अपने घर से कर सकती हैं. किसी कंपनी से जुड़कर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं.

प्रमुख संस्थान

■ सोफिया पॉलिटेक्निक, मुंबई.
■ पर्ल ऐकेडमी ऑफ फैशन, नई दिल्ली.
■ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंग्लोर, हैदराबाद और गांधीनगर.
■ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, कोलकाता.
■ सी ई पी जेड इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मुंबई.

सैलरी पैकेज

इस फील्ड में बहुत पैसा है. शुरुआत में आपको किसी के अंडर रहकर काम करना पड़ता है, ताकि आप इस दुनिया की कुछ प्रैक्टिक बातें सीख सकें. स्टार्टिंग में आहपको 10-15 हज़ार मिलते हैं. किसी बड़े डिज़ाइनर का साथ मिल जाए, तो ये सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है. अनुभव और कॉन्टैक्ट्स के बाद आप अपना ब्रैंड स्टैब्लिश करने के साथ ज़्यादा कमा सकते हैं.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण का क्या होगा?

सहारनपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने, दबाने के लिए नहीं हैं। वे देश के समग्र विकास के लिए हैं। पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके नेता हर जगह जाकर ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं? जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण का क्या होगा। सबके वोट के अधिकार का क्या होगा? इसका जवाब दें। ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत। हम तो वैसे भी नहीं डरते। प्रियंका ने कहा कि या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको पता है कि इन्हें 400 पार मिलने वाले हैं...अगर देश में ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ न हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकते, उससे भी कम सीटें लेंगे। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया।

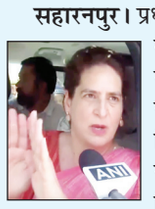

परमाणु हथियारों को नष्ट करने माकपा के वादे पर रुख साफ करे कांग्रेस : राजनाथ सिंह

तिरुवनंतपुरम। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने देश में परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के चुनावी घोषणापत्र के वादे के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस से अपना रुख जाहिर करने की मांग की। सिंह ने आरोप लगाया कि भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात करना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश को कमजोर करने के लिए गहरी साजिश रची जा रही है। राज्य के कासरगोड जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने मांग की कि कांग्रेस को परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के घोषणापत्र में किए गए वादे पर अपना रुख जाहिर करना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने ही देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था।

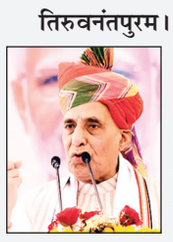

आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बीआरएस प्रमुख को नोटिस

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जी निरंजन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कहा कि केसीआर ने 5 अप्रैल को सिरसिला में अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। आयोग ने यह भी कहा कि केसीआर को उनके भाषण के संबंध में पहले भी हमारी ओर से कई सलाह और निर्देश जारी किए गए थे। आयोग को 6 अप्रैल को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी. निरंजन से एक शिकायत मिली थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि के चंद्रशेखर राव ने सिरसिला में अपनी प्रेस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे।

लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को झारखंड में झटका

रांची। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी के कद्दावर नेता राधाकृष्ण किशोर ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। किशोर ने अपना इस्तीफा राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि गठबंधन के तहत मात्र पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से प्रदेश राजद के कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चतरा से गिरिनाथ सिंह को लोकसभा का टिकट दिया जाता, तो सवर्णों में उसका अच्छा संदेश जाता। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि राजद ने कार्यकर्ताओं की भवनाओं का कद्र नहीं किया। समाज को बांटने वाली इस संस्कृति से मैं आहत हूं और इसलिए राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। राजद नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राजद के समाजिक न्याय और सभी वर्गों के उत्थान के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वर्ष 2020 में मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी।

पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को फोन पर मिली धमकी

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। खडसे, जो वर्तमान में राकांपा (शरद गुट) के साथ हैं, ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह जल्द ही भाजपा में लौटेंगे। पुलिस ने बताया कि सोमवार को खडसे को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा फोन आया जिसके बाद उन्होंने जलगांव जिले में मुक्ताई नगर थाने में पुलिस को इसकी शिकायत की। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार फोन करने वाले व्यक्ति ने खडसे को धमकी देते हुए गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम का उल्लेख किया। अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि खडसे की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर बोला हमला

मोदी तो भ्रष्टाचार के महारथी हैं : राहुल

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार का चैंपियन हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई चुनावी बांड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस करते हुए वायनाड सांसद ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का दिया गया हालिया साक्षात्कार स्क्रिप्टेड और फ्लॉप शो था।

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था। वह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ओर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए लाया गया लकिन राजनीति को स्वच्छ करने के लिए आप उन तारीखों को छिपाते हैं, जब आपने जबरन पैसे लिए? चुनावी बांड योजना को इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। पिछले महीने अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बांड खरीदने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम उजागर करने को कहा।

राहुल गांधी ने कहा, यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है। भारत के सभी कारोबारी इस बात को समझते और जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चाहे कितनी भी सफाई दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि एनडीए के नेतृत्व वाली भाजपा आगामी चुनावों में 150 सीटों का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी 180 के आसपास सीटें जीतेगी लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें मिलेंगी। हमें हर राज्य से रिपोर्ट मिल रही है कि हम सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह लोकसभा चुनाव अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बीजेपी का

सवाल है, बहुत अच्छा. मुझे जो भी आदेश मिलेगा, मैं उसका पालन करूंगा. हमारी पार्टी में ये सब (चयन) उम्मीदवार) निर्णय सीईसी द्वारा लिए जाते हैं।

इसी सुर में बात करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं रामनवमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आज हम गाजियाबाद में हैं और इस बार भारत गठबंधन गाजियाबाद से लेकर गाज़ीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा, आज किसान परेशान हैं क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले।

यादव ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया...बीजेपी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई...वे न केवल भ्रष्टाचारियों को (अपनी पार्टी में) ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों द्वारा कमाया गया पैसा भी अपने पास रख रहे हैं।

एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर चुनावी बांड योजना पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि जब ईमानदारी से विचार किया जाएगा तो हर किसी को पछतावा होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि चुनावी चंदे की योजना राजनीति में काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, हमारे देश में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि चुनावों में काले धन के जरिए एक खतरनाक खेल होता है। देश के चुनावों में काले धन का खेल खत्म हो, यह चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी पार्टी भी खर्च करती है, सभी पार्टियां, उम्मीदवार खर्च करते हैं और पैसा लोगों से लेना पड़ता है। मैं चाहता था कि हम कुछ प्रयास करें, हमारा चुनाव इस काले धन से कैसे मुक्त हो पारदर्शिता हो? मेरे दिमाग में एक शुद्ध विचार था। हम एक छोटा सा रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह बिल्कुल सही रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद चुनावी बांड खरीदने वाली 16 कंपनियों द्वारा किए गए कुल दान में से केवल 37 प्रतिशत राशि भाजपा को और 63 प्रतिशत विपक्षी दलों को गई।

उन्होंने कहा, मुझे याद है नब्बे के दशक में भाजपा को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पैसे नहीं होते थे। जो देना चाहते थे उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे ये सब पता था। अब देखिए, अगर चुनावी बांड नहीं होता तो सिस्टम के पास ये पता लगाने की ताकत थी कि पैसा कैसे आया और कहां गया। यह चुनावी बांड की सफलता की कहानी है।

नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको पता चल रहा है कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। इस प्रक्रिया में जो हुआ वह अच्छा था या बुरा यह बहस का मुद्दा हो सकता है। मैं यह कभी नहीं कहता कि निर्णय लेने में कोई कमी नहीं थी। चर्चा करके, सुधार करके हम सीखते हैं लेकिन आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है, इसलिए मैं कहता हूं, जब वे ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी को पछतावा होगा।

प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस संविधान को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, एक ओर आरएसएस और भाजपा संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई दूसरी नंबर पर है, लेकिन भाजपा इन्हें छोड़कर ध्यान भटकाने में लगी हुई है। न तो प्रधानमंत्री और न ही भाजपा इन गंभीर मुद्दों पर बात करने का प्रयास करते हैं।

नलबाड़ी रैली में प्रधानमंत्री ने किए बड़े वादे

गरीबों को मिलेंगे 3 करोड़ नए घर बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज

नलबाड़ी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन 17 अप्रैल को आक्रामक प्रचार जारी रखा। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होने वाला है और शुक्रवार को मतदान के लिए निर्धारित सभी राज्यों में रैलियों और रोड शो के लिए देश के शीर्ष नेताओं की पूरी सूची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो चुनावी रैलियां करने का प्रोग्राम था। इसमें से सबसे पहले पीएम मोदी ने असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया है तब मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है।

पीएम मोदी ने कहा कि यहां आप सभी का प्यार, उत्साह और भव्य उपस्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि 4 जून को क्या होने वाला है! तभी तो लोग कहते हैं, 4 जून, 400 पार! फिर एक बार, मोदी सरकार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में जनता से कई बड़े वादे किए। उन्होंने ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को भाजपा के अलावा पूर्व की सरकारों सिर्फ समस्याएं ही दी हैं। उन्होंने दावा किया कि अब देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चल रही है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में मनाए जा रहे श्री राम जन्मोत्सव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा की भारत के इतिहास में 500 वर्षों में ऐसा दिन आया है जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य रूप में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं और कहा कि अयोध्या नगरी अतुलनीय आनंद में है क्योंकि वहां राम मंदिर बनने के बाद यह पहली रामनवमी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी एक मील का पत्थर है जो सदियों की भक्ति को आशा और प्रगति के एक नए युग से जोड़ती है। यह वह दिन है जिसका करोड़ों भारतीयों को इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक वाद्य यंत्र पर हाथ आजमाते हुए स्थानीय सभ्यता से खुद को जोड़ने का प्रयास किया। मंच से पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रैली में मंच से पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। नॉर्थ ईस्ट खुद मोदी की गारंटी का गवाह है। पीएम ने कहा, जिस नॉर्थ-ईस्ट को कांग्रेस ने केवल समस्याएं दी थीं। भाजपा ने इसे संभावनाओं के स्रोत में बदल दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया और मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर सकी, मोदी ने 10 वर्षों में किया। पीएम ने आगे कहा, एनडीए ने देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने और उन्हें वे सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है जिनके वे हकदार हैं। अगले 5 वर्षों में, 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। ये गरीबों और सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलेंगे...मोदी ने गारंटी दी है कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कोई भी भेदभाव किए बिना मोदी उनके इलाज का ख्याल रखेंगे।

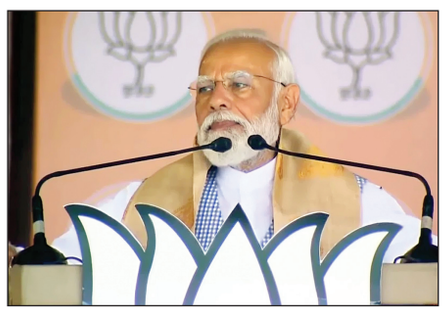

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा विराट कर सकते हैं ओपनिंग

मुंबई। आईपीएल 2024 के बाद क्रिकेट फैंस के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं।

खबरों के मुताबिक बीसीसीआई की बैठक के दौरान टीम को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। टी20 विश्व कप में अगर आप विराट कोहली को रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए देखें तो आश्चर्यचकित न हों। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कथित तौर पर विश्व प्रतियोगिता के लिए कोहली को रोहित के ओपनिंग पार्टनर के रूप में रखने की इच्छुक है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते मुंबई में हुई एक बैठक में कोहली को सलामी बल्लेबाज के रूप में रखने की संभावना पर गंभीरता से चर्चा की गई थी, जहां कप्तान रोहित, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और मुख्य सेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे। दरअसल, पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद जब रोहित, द्रविड़ और चयनकर्ताओं की बैठक हुई तो टी20 टीम में कोहली की जगह पक्की नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। कोहली ने अफगानिस्तान की घरेलू सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया। वह और रोहित लगभग दो वर्षों में पहली बार टी20ई में लौटे। उन्होंने दो मैचों में अपने पसंदीदा नंबर 3 स्थान पर बल्लेबाजी की, जिसमें यशस्वी जयसवाल ने रोहित के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की। लेकिन टी20 विश्व कप के आगामी संस्करण में यह बदल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहली टी20 विश्व कप में अपनी जगह के बारे में चयन समिति से स्पष्टता चाहते थे। कोहली आईपीएल के पिछले कुछ सीज़न में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए नियमित रूप से ओपनिंग करते रहे हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

एफआईआई ने मार्च तिमाही में बीएसई की सौ से ज्यादा कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी

नईदिल्ली। मार्च तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) ने बीएसई 500 की करीब 144 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। ऐस इक्विटी के पास उपलब्ध शुरुआती शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार मार्च तिमाही में एफआईआई खरीदारी की होड़ में थे। हालांकि जनवरी 2024 में 25,743 करोड़ रुपये के इक्विटी आउटफ्लो के साथ हुई, और मार्च में तेज उछाल के साथ 35,098 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ। एफपीआई ने अदाणी ग्रीन एनर्जी (18.03% से 18.15% तक), अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (14.72% से 14.98% तक), अदाणी पावर (15.86% से 15.91% तक), अदाणी टोटल गैस (13.06% से 13.12% तक) और अदाणी विल्मर (0.65% से 0.77% तक) सहित चुनिंदा अदाणी समूह की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी।

वेदांता को मिला 27 करोड़ रु. से ज्यादा का जीएसटी नोटिस

नईदिल्ली। वेदांता लिमिटेड को जीएसटी टैक्स का नोटिस मिला है। कंपनी ने इस बारे में मंगलवार को बताया कि वेदांता को वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 27.97 करोड़ रुपये के जीएसटी के जुर्माने का आदेश मिला है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये फाइन वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट रीकॉन्सिलेशंस से जुड़े विवाद से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 'कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, राउरकेला के कार्यालय से ये आदेश मिला है, जिसमें टैक्स की मांग और लागू ब्याज के साथ 27.97 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। इस मामले में कंपनी का कहना है कि वो इस विवाद से जुड़े मामले को निपटाने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों के साथ आदेश के बारे में अपील करेगी।

वोडाफोन आइडिया ने निवेशकों से जुटाए 5,400 करोड़ रुपये

नईदिल्ली। वोडाफोन आइडिया ने 5,400 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एंकर निवेशकों को 11 रुपये प्रति शेयर (प्राइस बैंड के टॉप-एंड) पर 4.9 बिलियन शेयर अलॉट किए हैं। एंकर कैटेगरी में कुल 74 अलग-अलग स्कीम्स में शेयर अलॉट किए गए। अमेरिका की तत्त्व पार्टनर्स ने 1,347 करोड़ रुपये मूल्य का सब्सक्रिप्शन लिया जो कि एंकर कैटेगरी का करीब एक चौथाई हिस्सा है। इसके अलावा अन्य बड़े ग्राहक Fidelity, Stichting, Redwheel, Motilal Oswal Mutual Fund और Troo Capital रहे। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) खुलने से एक दिन पहले एंकर अलॉटमेंट किया जाता है। क्योंकि बुधवार को बाजार में छुट्टी है, इसलिए वीआईएल का 18,000 करोड़ रुपये का एफपीओ, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और सोमवार को बंद होगा।

कंपनी इंडोनेशिया में विनिर्माण पर विचार कर रही है: टिम कुक

नईदिल्ली। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो से मुलाकात के बाद कहा कि कंपनी इंडोनेशिया में विनिर्माण पर विचार कर रही है। कुक ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, '' हमने देश में विनिर्माण को लेकर राष्ट्रपति की इच्छा के बारे में बात की और हम इस पर ध्यान देंगे।'' कुक ने कहा, '' मुझे लगता है कि इंडोनेशिया में निवेश की अनंत क्षमता है। मुझे लगता है कि निवेश करने के लिए बहुत से बेहतरीन स्थान हैं। हम निवेश कर रहे हैं। हम देश में विश्वास रखते हैं।'' कुक ने एक दिन पहले हनोई में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि एप्पल वियतनाम में अधिक निवेश करने और दक्षिण पूर्व एशियाई विनिर्माण केंद्र में आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक खर्च करने योजना बना रहा है।

भारत की जीडीपी अगले 50 वर्षों में 52 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर होने की संभावना

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

'आधार' ने तो देश के समस्त नागरिकों की एक अलग पहचान ही बना दी है। यूपीआई प्लेटफोर्म ने भी इस संदर्भ में ग्रामीण इलाकों में रोकड़ के उपयोग को कम कर डिजिटल प्लेटफोर्म पर वित्तीय व्यवहारों को हस्तांतरित किया है। छोटे छोटे व्यवसाईयों, किसानों, सामान्य नागरिकों को भी वित्तीय प्लेटफोर्म पर लाने में यह डिजिटलीकरण बहुत सफल रहा है। इससे वित्तीय समावेशन का कार्य भी आसान बन पड़ा है। भारत में डिजिटल व्यवहारों की संख्या आज संयुक्त रूप से अमेरिका, चीन एवं यूरोप से भी अधिक है। जबकि अमेरिका, चीन एवं यूरोप के देश भारत से अधिक विकसित देश हैं। इससे यह झलकता है कि भारत ने डिजिटलीकरण के मामले में पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है। अब तो भारत का यूपीआई सिस्टम अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण के मामले में अपनी धाक जमाने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का यूपीआई सिस्टम सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका एवं यूएई में लागू किया जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय यूपीआई सिस्टम का उद्घाटन किया था, ताकि फ्रांस में जाने वाले पर्यटक यूपीआई सिस्टम के माध्यम से फ्रान्स में वित्तीय व्यवहार कर सकें। न्यूजीलैंड में भी यूपीआई को लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

उक्त संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा कारण है चीन के, विस्तरवादी नीतियों के चलते, विश्व के अन्य देशों के साथ लगातार खराब होते सम्बंध। आज विश्व के कई देश चीन के साथ आर्थिक व्यवहार करने से कतराने लगे

हैं। यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास को गति दे सकती है क्योंकि चीन+1 की नीति का अनुपालन विश्व के कई विकसित देश आज करने लगे हैं एवं ये देश भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी इकाईयों को स्थापित करते जा रहे हैं। ताइवान आदि देशों पर चीन की नीति की पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है। चीन के अपने बॉर्डर पर लगने वाले लगभग समस्त देशों के साथ चीन के सम्बंध अच्छे नहीं हैं। इन देशों का चीन पर अब भरोसा समाप्त सा होता जा रहा है। ऐपल एवं टेस्ला जैसी कम्पनियां अब भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर रही हैं। ऐपल ने तो अपने आईफोन-15 का उत्पादन भारत में चालू भी कर दिया है। इससे भारत में न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं बल्कि विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। आज भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। साथ ही, आज भारत का पूंजी बाजार (स्टॉक मार्केट) विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है।

भारत द्वारा अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस मद पर खर्च की गई थी। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, जम्मू कश्मीर जैसे अन्य कई धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है जिससे रोज़गार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। एयरपोर्ट की संख्या पिछले 10 वर्षों में दुगने से भी अधिक होकर 150 तक पहुंच गई है और इसे वर्ष 2025 तक 200 की संख्या तक ले जाया जा रहा है। रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। भारत के बड़े शहरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा रहा है। आज भारत का रोड नेट्वर्क चीन से भी अधिक होकर विश्व में केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत सरकार की वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के बीच देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च करने की योजना है। इस प्रकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी सम्भावना भी व्यक्त की जा रही है।

तपती धूप के साथ लगातार चढ़ेगा पारा

रायपुर। सूबे की राजधानी रायपुर में बदली-बारिश का दौर थम गया है। शहर के अंदर मौसम पूरी तरह से साफ होने के बाद तापमान फिर बढ़ रहा है। रायपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर का मौसम शुष्?क ही रहेगा। सुबह से तीखी धूप निकली हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि

रायपुर में 40 के क़रीब पहुंचा पार

अगले तीन दिनों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा।

मंगलवार के बाद आज बुधवार को भी रायपुर में सुबह से तीखी धूप है। मंगलवार को दिनभर यहां चिलचिलाती धूप और उमस ने परेशान किया। नमी 71 प्रतिशत तक थी। अधिकतम तापमान रायपुर में 39.8, माना में 39, बिलासपुर में 40.6, राजनांदगांव में 40.5, पेण्ड्रारोड में 38.3, अंबिकापुर में 37.9, जगदलपुर में 39.4 और दुर्ग में 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी में बीती रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था।

मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ 64 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका पूर्वी बिहार से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक झारखंड, उड़ीसा होते हुए है।

प्रदेश में 17 अप्रैल को मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि का क्रम लगातार जारी रहने की संभावना है।

नक्सल मुठभेड़ के बहाने उप मुख्यमंत्री साव ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा-

अवरूद्ध कर रखा था बस्तर का विकास

रायपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर नक्सल मुठभेड़ के हवाले से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने बस्तर में विकास कार्य को अवरूद्ध कर रखा था. इनकी सरकार में नक्सली फले फूले हैं. गांव से शहरों तक नक्सलियों का विस्तार हुआ है. जबकि हमने नक्सलियों को सीमित क्षेत्र में खदेड़ दिया था.

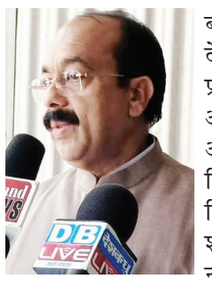

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांकेर में सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षा बलों ने बहादुरी से मुठभेड़ को अंजाम दिया है. इसके लिए जवानों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. साव ने कहा कि बस्तर के सुदूर अंचल तक विकास कार्य पहुंचे, इसके लिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है. गृहमंत्री अमित शाह मिशन मोड में काम कर रहे हैं. वे हमें लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं. यहां डबल इंजन की सरकार है. बस्तर आने वाले समय में विकास से जुड़ेगा. साव ने कहा कि विकास और शांति के लिए कानून का राज व नक्सली उन्मूलन आवश्यक है.

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेत्रियों के आरोपों पर राधिका खेड़ा का पलटवार, कहा

रामनवमी के दिन तो झूठ नहीं बोलना था

रायपुर। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई नेत्रियों के प्रेस वार्ता में पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि रामनवमी जैसे पवित्र दिन को तो छोड़ ही देना था, आज भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. भाजपा की चाइनीज़ गारंटी पर कांग्रेस छोड़कर गई हैं. पार्टी ने पहचान दी, पहचान देने वाली मां होती है, और मां को धोखा देता है, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं.

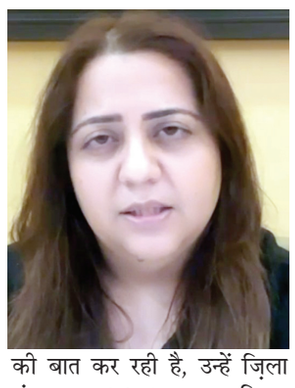

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि जो महिलायें अपमान और दुर्व्यवहार

की बात कर रही है, उन्हें ज़िला पंचायत अध्यक्ष, नगरनिगम अध्यक्ष , महापौर जैसे पद किसने दिए. अपमान करते हुए किसी को ऐसे पद पर पहुँचने के लिये ना मदद की जाती है, ना टिकट दी जाती है. जिस पार्टी में ये महिलाएं शामिल हुई, उनकी सरकार में छत्तीसगढ़ क्राइम के मामले में टॉप फाइव में था. हमारी सरकार क्राइम के मामलों में राज्य को बीसवें से भी नीचे लाई.

खेड़ा ने कहा कि इन महिलाओं को ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जिस पार्टी में ये गई, उस पार्टी ने भानुप्रतापुर के उप चुनाव में पॉक्सो एक्यूस्ड को टिकट दिया. कांकेर के प्रत्याशी के ऊपर आदिवासी महिला उत्पीड़न का मामला है, वो महिला भी कहां है ये किसी को नहीं पता. जो पार्टी खुद शोषण करने, अभद्रता करने और ऐसे लोगों को टिकट देने में लिप्त है, ये महिलाएं ऐसे पार्टी में जाकर सेफ महसूस कर रही हैं. महिलाओं द्वारा कांग्रेस पार्टी पर झूठे वादों के आरोप पर राधिका खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के अधूरे वादों पर बात करने वाली महिलाएँ ये भूल गई कि 500 रुपए के सिलिंडर का जानता को आज भी इंतज़ार हैं. महतारी वंदन का वादा मोदीजी करके गए, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ़ 30 प्रतिशत महिलाओं को मिला, 70 प्रतिशत महिलाए 1000 रुपए के इंतज़ार में हैं.

यूपीएससी टॉपर्स से मुख्यमंत्री साय ने की बात, शुभकामनाएं देते हुए की उनके प्रगति की कामना

रायपुर। यूपीएससी मेन्स-2023 का परिणाम मंगलवार को जारी हुआ. परीक्षा में इस बार छत्तीसगढ़ के चार प्रतिभागियों ने स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है. इनमें से अनुषा पिल्लै, अभिषेक डेंगे, प्रीतेश सिंह राजपूत और रश्मि पैकरा शामिल हैं. वहीं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूपीएससी परीक्षा-2023 में छ्त्तीसगढ़ के सफल अभ्यर्थियों रायपुर की पूर्वा अग्रवाल, अनुषा पिल्लै, अभिषेक डेंगे, नेहा ब्याडवाल, जगदलपुर की जिज्ञासा सहारे और बलरामपुर की रश्मि पैकरा से बात कर अपनी शुभकामनाएं दी और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की.

बता दें कि परीक्षा के जरिए कुल 1016 प्रतिभागी चयनित हुए हैं. इनमें से टॉप-20 में 15 लड़कों और 5 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है. सूची में पहले स्थान पर लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव हैं. वहीं दूसरे स्थान पर अनिमेष प्रधान और तीसरे पर डोनुरु अनन्या रेड्डी हैं.

परीक्षा में 202 रैंक हासिल करने वाली अनुषा पिल्लै आईएएस रेणु पिल्लै और सेवानिवृत्त आईपीएस संजय पिल्लै की बेटी हैं. अनुषा के पहले पिल्लै दंपती के बेटे अक्षय पिल्लै ने 2021 यूपीएससी 51 रैंक हासिल किया था. वर्तमान में अक्षय पिल्लै उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर हैं.

यूपीएससी मेन्स-2023 में चयनित छत्तीसगढ़ के अन्य प्रतिभागियों में से प्रीतेश सिंह राजपूत ने 697 रैंक हासिल किया है. लोरमी के रहने वाले प्रीतेश वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर पदस्थ हैं. वहीं एनआईटी पास आउट अभिषेक डेंगे रायपुर के हैं, और रश्मि पैकरा बलरामपुर की रहने वाली हैं.

बस्तर का आखिरी गांव, माना जाता है नक्सलियों का गढ़,

पहली बार होगी लोस चुनाव के लिए वोटिंग

जगदलपुर/रायपुर। नक्सलियों के गढ़ कह जाने वाले चांदामेटा

में पहली बार देश के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव को लेकर इस इलाके के ग्रामीण मतदान करेंगे. यह वही इलाका है जहां नक्सलियों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी, क्योंकि बस्तर जिले का यह अंतिम गांव पड़ता हैं और यहीं से तुलसी डोंगरी पहाड़ियों से ओडिशा लग जाता है. ऐसे में यहां एक समय नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप संचालित होता था .लेकिन अब हालात बदल गए हैं. इस गांव तक पहुंचने के लिए जरूर सड़क भी बन गया है, लेकिन आज भी यहां के ग्रामीणों ने अपने किसी भी जनप्रतिनिधि या नेताओं को आज तक नहीं देखा है. 19 अप्रैल को दूसरी बार चांदामेटा के ग्रामीण मतदान करने जा रहे हैं.

ग्रामीणों ने नहीं देखा नेताओं का चेहरा- सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के ग्रामीणों को यह तक नहीं मालूम कि यह चुनाव कौन सा है. न तो उन्होंने विधायक को देखा और न ही सांसद को. नक्सल ख़ौफ के चलते अब तक कोई भी पार्टी का प्रत्याशी यहां प्रचार करने नहीं आया. इस गांव में पार्टी के झंडे पूरी तरह से गायब है. आज भी यहां के ग्रामीण झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं.

छत्तीसगढ़ पुलिस का लक्ष्मण केवट, जिससे नक्सलियों की कांपती है रूह, अब तक करीब 50 नक्सली कर चुके ढेर

रायपुर। लक्ष्मण केवट, छत्तीसगढ़ पुलिस का ऐसा नाम जो नक्सलियों में दहशत पैदा करता है। जिस मुठभेड़ में लक्ष्मण है, उसमें नक्सलियों को भागना पड़ेगा या जान खोना पड़ेगा। एक बार फिर ये बात साबित हुई, क्योंकि कांकेर के मुठभेड़ में लक्ष्मण केवट शामिल थे और ष्ठञ्जस्न टीम का नेतृत्व कर रहे थे। नतीजा छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सफलता पुलिस को मिली।

एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। क्या थी पुलिस के पास सूचना, कैसे बने रणनीति। जब जवान नक्सलियों को घेरने पहाड़ पर चढ़ना शुरू

कर रहे थे, तभी गांव में क्यों पटाखे फूटने लगे। नक्सलियों की हर दांव कैसे विफल होते चले गई। चारों तरफ से घेर कर कैसे नक्सलियों को मार गिराया गया। ग्राउंड जीरो पर हुई हर घटना की आंखों देखी रिपोर्ट, लक्ष्मण केवट की जुबानी। सुनिए ढ्ढक्च्24 के संवाददाता ने 6 बार के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार जीतने वाले, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट से क्या बात की और उन्होंने क्या बताया।

बता दें कि सुरक्षाबलों ने कांकेर के छोटे बैठिया के जंगल के माड़ क्षेत्र में बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 29 माओवादियों को ढेर कर दिया हैं। इस मुठभेड़ में बड़ा माओ नेता शंकर राव भी मारा गया हैं, जबकि कई दूसरे इनामी नक्सली भी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। मुठभेड़ में तीन जवान भी घायल हुए हैं जिन्हे रायपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा को मिला सूबे के 2 लाख 80 हजार कर्मचारियों का समर्थन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 2 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इस संबंध में एक पत्र भी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने ज़ारी किया है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अनियमित कर्मचारियों का आभार जताया है। सिंहदेव ने 2 लाख 80 हजार कर्मचारियों द्वारा भाजपा को समर्थन देने हेतु आभार जताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश के 2,80,000 अनियमित कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों ने भाजपा को अपना वोट देने के संबंध में समर्थन पत्र दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी एवं विष्णु सरकार के सुशासन पर अपना विश्वास जताने वाले अनियमित कर्मचारियों का आभार। निश्चित ही भाजपा ही देशवासियों की चिंता कर हर वर्ग को न्याय देने का काम करती है और करती रहेगी।

जंवारा विसर्जन करने तेज धूप में कलश थामकर नंगे पैर निकली महिलाएं

रायपुर। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन जोत

जंवारा विसर्जन में श्रद्धा भक्ति के साथ उत्साह से महिलाएं शामिल हुईं। सिर पर जोत जवारा कलश थामकर महिलाएं निकली। तेज धूप में कलश थामकर नंगे पैर चल रही महिलाओं के पैरों को जलन से बचाने सेवादार पानी का छिड़काव करते चल रहे थे। अनेक यात्राओं के पीछे टैंकर की व्यवस्था की गई थी। कुछ मार्गों पर कई लोगों ने अपने घर से पाइप के माध्यम से जल का छिड़काव करके राहत देने का कार्य किया। जोत जवारा विसर्जन यात्रा का नजारा बढ़ई पारा, तात्यापारा, सत्ती बाजार, पुरानी बस्ती इलाके में दिखाई दिया। जोत का विसर्जन कंकाली तालाब में किया गया। घर-घर में स्थापित घट कलश, जोत-जंवारा का विसर्जन करने की परंपरा निभाई गई। अनेक मोहल्लों से जंवारा विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं ने सांग-बाणा धारण किया। दोनों गाल, छाती, हाथ, होंठ, जीभ को नुकीले तीरों से बेधकर श्रद्धा भक्ति के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। कंकाली मंदिर के सामने स्थित कंकाली तालाब में जोत जंवारा का विसर्जन सुबह से शाम तक चलेगा। देवी मंदिरों में कन्याओं का पूजन करके भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया।

मतदाताओं को जागरूक करने कैनोइंग क्लब के साथ दिया बोट पर वोट का संदेश

रायपुर। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में ज़िला प्रशासन द्वारा आम मतदाताओं को 7 मई को मतदान का संदेश देने संचालित अभियान के तहत नगर निगम कमिश्नर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जोन -4 की टीम ने कैनोइंग क्लब के साथ बूढ़ातालाब विवेकानंद सरोवर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया । तैराकों ने अपने साथ बोट में मतदान संदेश के प्ले काड्र्स के साथ अपने करतब भी दिखाए। इस दौरान जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा , सहायक अभियंता पद्माकर श्रीवास ने मॉर्निंग वॉक पर निकले नागरिकों को मतदान शपथ दिलाई। अद्भुत प्रदर्शन को देखने इस दौरान कई नागरिक उपस्थित थे ।

रायपुर में रेलवे ट्रैक पर युवक की सिर कटी लाश मिली

रायपुर। राजधानी रायपुर के मोवा रेलवे क्रासिंग से कुछ दूर एक सिर कटी लाश मिलने का मामला सामने आया है। मोवा रेलवे ट्रैक पर सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस

मौके पर पहुंच गई और घटना का जायजा लिया। हालांकि युवक की हत्या हुई है आत्महत्या इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल, यह मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। मोवा रेलवे क्रासिंग से कुछ दूर पर रेलवे ट्रैक पर एक सिर कटी लाश मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पंडरी थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान गांधी नगर निवासी गोलू सोरठे के रूप में हुई है। मृतक बिजली फिटिंग का काम करता था। मामले की जांच कर रहे पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि मोवा रेलवे क्रासिंग के पास पटरी पर एक सिर कटा शव पड़ा है। वे मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़ित का सिर धड़ से कटा हुआ मिला। फिलहाल युवक की हत्या हुई है या आत्महत्या है, इसे जांच की जा रही है।

पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए स्वीप अंतर्गत निकाली गई अनोखी तरकीब

रायपुर। जिले में पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु स्वीप अंतर्गत अनोखी तरकीब निकाली गई है। पलायन करने वाले परिवारों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 26 अप्रैल मतदान दिवस के दिन वापस घर आकर मतदान करने की गुजारिश की जा रही है। बीएलओ द्वारा मतदान पर्ची घर-घर जाकर दिया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान पलायन करने वाले ऐसे मतदाताओं का चिन्हांकन किया गया है। स्नेह एवं अपनत्व के महौल में बीएलओ न केवल घर का हाल चाल पूछ रहीं हैं, बल्कि 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए आमंत्रित कर रहीं हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वीप अंतर्गत मतदान जागरूकता के लिए विविध आयोजन किए जा रहे हैं तथा व्यापक स्तर पर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देशन में मतदान जागरूकता के लिए स्वीप टीम द्वारा ऊर्जा एवं उत्साह के साथ कार्य किया जा रहा है। जिले में पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु अनोखी तरकीब के अंतर्गत वीडियो कॉलिंग करते हुए मतदान करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से फोन करने का असर यह रहा है कि उनमें यह भावना जागृत हुई है कि वोट की कीमत है.

आरपीएफ और रायपुर पुलिस ने पकड़ा 4 लाख का गांजा

रायपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह के द्वारा निजात अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों पर लगातार कार्र्वाई करने निर्देशित किया गया था, उसी तारतम्य में थाना मंदिर हसौद पुलिस को मुखबीर सूचना मिली की दो लडके भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर ओडिशा से सूरत जा रहे है उपरोक्त सूचना से तुरंत वरिष्ठ अधिकारियो को एवं रेलवे सुरक्षा बल चौंकी मंदिरहसौद की टास्क टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक तरूणा साहू की टीम को अवगत कराया गया एवं रेलवे सुरक्षा बल टास्क टीम एवं थाना मंदिरहसौद टीम द्वारा मुखबीर के बताये अनुसार मंदिर हसौद चौंक पर दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकडा गया. पूछताछ करने पर दोनो ने अपना अपना नाम क्रमश: 01 संतोष ऊर्फ हाडू बंधु बेहरा पिता स्व0 डाको बेहरा उम्र 25 साल साकिन मंगलपुर (योगलपुर) थाना आस्का जिला गंजाम ओडिशा 2 सागर जेना पिता बाकुनी जेना उम्र 19 वर्ष साकिन कुलासरा पाली (नुवासाही) थाना आस्का जिला गंजाम उडीसा बताया दोनो के पास दो नग ट्राली बैग एवं एक पिठ्ठू बैग में कुल 15 पैकेट

मादक पदार्थ गांजा मिला जिन्हे पुछताछ करने पर मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से बिक्री करने के प्रयोजन से ओडिसा से सूरत परिवहन करना बताये, आरोपीगण के कब्जे से कुल 15 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, कुल वजन 30.909 किग्रा कीमती 4,63,635 रूपए एवं दो एन्ड्राईड मोबाईल कीमती 20,000 रूपये कुल जुमला कीमती 4,83,635 रूपये को जप्त किया गया. उपरोक्त कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल चौंकी मंदिरहसौद के टास्क टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक तरूणा साहू के निर्देशन में प्रधान आरक्षक वृंदालाल यादव एवं आरक्षक शमशेर सिंह एवं थाना मंदिर हसौद के सउनि विनोद सिंह, आरक्षक राकेश साहू, आरक्षक राकेश हिरवानी, आरक्षक निहाली साहू की भूमिका सराहनीय रही.

राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन से पहले करना होगा यह काम

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश में हो रहे सातों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत तीनों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा।

आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल तथा तीसरे चरण में 6 और 7 मई को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.